लखनऊ

रविवार, 13 सितंबर, 203

वर्ष : 12 । अंक: 20

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

अगर आप सच बोलेंगे, तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा, लखनऊ में हुई कोर ग्रुप की बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। पार्टी के कोर ग्रुप ने शुक्रवार शाम लखनऊ में एक अहम बैठक की। BJP के राज्य मुख्यालय में हुई यह बैठक दो घंटे से ज़्यादा समय तक चली और इसमें पार्टी की चुनावी तैयारियों, संगठनात्मक रणनीति और आने वाले अभियानों पर चर्चा हुई। यह बैठक उत्तर प्रदेश BJP द्वारा अपने क्षेत्रीय और फ्रंटल संगठनों के प्रभारियों (जिनमें छह क्षेत्रीय प्रभारी भी शामिल हैं) की घोषणा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े, सह-प्रभारी जगदीश पटेल, राज्य बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक शामिल हुए। बैठक के बाद पंकज चौधरी ने बताया कि नेताओं ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों और आने वाले महीनों में पार्टी की दिशा को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मुख्य रूप से 17 सितंबर से शुरू होने वाले अभियानों पर चर्चा हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ मेल खाते हैं। पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी 17 सितंबर से 'सेवा संकल्प' और 'सुशासन' अभियान शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि बैठक में इन अभियानों की तैयारियों और उन्हें लोगों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। चौधरी ने कहा कि हमने बीएल संतोष जी, बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और महासचिव विनोद तावड़े जी, सह-प्रभारी जगदीश पटेल जी, मुख्यमंत्री और दोनों उप-मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा की।

मल्लिकार्जुन खरगे का गुजरात जल संकट पर भाजपा पर हमला, CAG रिपोर्ट का दिया हवाला

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुजरात में पेयजल की स्थिति को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "हर घर जल" के दावे दूषित पानी में बह गए हैं। खरगे ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया कि गुजरात में 10 में से करीब नौ नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान शुरू की गई 'सुजलाम-सुफलाम' योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2004 में इसका जोर-शोर से प्रचार किया गया था, लेकिन आज भी राज्य के कई हिस्सों में लोग पानी के लिए परेशान हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इसी तरह के दावों को 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। उन्होंने दावा किया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट ने वर्ष 2022 में गुजरात में 100 प्रतिशत नल कनेक्शन के किए गए दावे पर सवाल उठाए हैं और करीब 14 लाख घर अब भी पानी का इंतजार कर रहे हैं। खरगे ने अहमदाबाद जिले के धोलका में दूषित पानी पीने के कारण 54 लोगों की कैंसर से मौत होने संबंधी हालिया खबर का भी हवाला दिया। उन्होंने सौराष्ट्र के राजकोट और जामनगर तथा कच्छ-सौराष्ट्र के अन्य इलाकों में पेयजल संकट और किसानों के सूखे से जूझने का दावा किया। खरगे ने कहा कि गुजरात की जनता को 2047 तक 'विकसित भारत' का सपना दिखाया जा रहा है।

समुद्री सुरक्षा, ग्लोबल साउथ और यूएनएससी में सुधार

पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें

हमें अगले 20 सालों के लिए एक नए और बड़े लक्ष्य वाले एजेंडे पर काम करने की ज़रूरत है। हमें इस प्रक्रिया की शुरुआत अपने अंदरूनी कामकाज के तरीकों से करनी चाहिए। भले ही ब्रिक्स की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है, लेकिन इससे हमारे संस्थागत कामकाज की रफ़्तार पर असर नहीं पड़ना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है। इस सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब संगठन को अपनी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस नतीजों में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने अगले 20 वर्षों के लिए महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने और ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी भारत की प्राथमिकताएं रही हैं। कोशिश की गई कि ब्रिक्स सहयोग को केवल सरकारों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे आम लोगों से भी जोड़ा जाए। इसी उद्देश्य से 350 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया गया और करीब 30 शहरों में सदस्य देशों की टीमों का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की अध्यक्षता में सहयोग देने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस साल का शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक है, क्योंकि ब्रिक्स अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है।

20 साल में ब्रिक्स ने बनाई अलग पहचान

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दो दशकों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि सदस्य देश एक-दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और सहमति के आधार पर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब समय आ गया है कि ब्रिक्स में मौजूद हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदला जाए।

अगले 20 साल के लिए तैयार करना होगा एजेंडा

प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स को आने वाले दो दशकों के लिए महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत संगठन के अपने कामकाज के तरीके में सुधार से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर साल बदलती है, लेकिन इसके कारण संगठन की संस्थागत प्रगति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जिससे अध्यक्षता बदलने के बावजूद फैसलों और पहलों में निरंतरता बनी रहे।

ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए 10 प्रस्तावों का सुझाव

पीएम ने आगे कहा, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल तैयार करें, जिसे हम अगली समिट तक एक ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप का रूप दे सकते हैं। इस रोडमैप को बनाने में हमें तीन मुख्य पहलुओं- रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग का ध्यान रखना होगा। पहला- रिप्रेजेंटेशन में यूएनएससी में सुधार अब टाला नहीं जा सकता। टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन से हमें इस जोड़ना होगा। वित्तीय संस्थानों में वोटिंग पावर, इकोनॉमिक नीति आज की असलियत के आधार पर होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक को गति देते हैं उन्हें उचित भूमिका मिलनी चाहिए। वैश्विक संस्थानों में तभी लोगों का विश्वास बनेगा, जब हम कलेक्टिव रिस्पॉन्स पर ध्यान देंगे। सीफेयर का वैश्विक व्यापार में बड़ा योगदान है। लेकिन अक्सर उन्हें मुश्किल आती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम आपात मैरीटाइम व्यवस्था बना सकते हैं।

ग्लोबल साउथ को नियम निर्माता बनाने पर जोर

भविष्य में रूल मेकिंग के लिए वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करना अहम है। एआई, क्रिटिकल तकनीक, आदि भविष्य की नीति और नियम तय कर रहे हैं। हमें ग्लोबल साउथ को रूल मेकर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सुखद संयोग से आज यूएन डे फॉर साउथ कोऑपरेशन है। इस दिन पर हमारी ओर से ऐसा निर्णय लिया जाना अहम है। भारत इस मामले में लीड लेने के लिए तैयार है। इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। यदि भविष्य हमारा है, तो इसका निर्णय लेने का अधिकार भी हमारा होना चाहिए।

ग्लोबल साउथ को नियम निर्माता बनाने पर जोर

भविष्य में रूल मेकिंग के लिए वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करना अहम है। एआई, क्रिटिकल तकनीक, आदि भविष्य की नीति और नियम तय कर रहे हैं। हमें ग्लोबल साउथ को रूल मेकर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सुखद संयोग से आज यूएन डे फॉर साउथ कोऑपरेशन है। इस दिन पर हमारी ओर से ऐसा निर्णय लिया जाना अहम है। भारत इस मामले में लीड लेने के लिए तैयार है। इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। यदि भविष्य हमारा है, तो इसका निर्णय लेने का अधिकार भी हमारा होना चाहिए।

पीएम मोदी-पुतिन की मुलाकात, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में शनिवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष, कौशल गतिशीलता और जन-जन के संपर्क समेत भारत-रूस सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल गतिशीलता और लोगों के बीच संपर्क से जुड़े क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने 9 से 11 सितम्बर तक भारत में पहली बार आयोजित रूस की अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी 'इनोप्रोम इंडिया' का स्वागत किया और इसे द्विपक्षीय व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और पुतिन ने 'इनोप्रोम इंडिया' प्रदर्शनी का दौरा किया और इसमें भाग लेने वाले हितधारकों से बातचीत की। प्रदर्शनी में भारत और रूस के औद्योगिक एवं कारोबारी सहयोग से जुड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों पर भारत-रूस सहयोग, विशेष रूप से भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सहयोग को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया। इसके अलावा पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र के संघर्षों समेत आपसी हित से जुड़े प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इन संघर्षों के समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की।

ब्रिक्स समिट में दिल्ली घोषणापत्र सर्वसम्मति से पास

भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर, शनिवार को ब्रिक्स समिट में 'दिल्ली घोषणापत्र' को अपनाया गया। इसमें भविष्य की टेक्नोलॉजी और उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों के विकास में 'ग्लोबल साउथ' की समान भागीदारी की मांग की गई। भारत मंडपम में समिट के दौरान यह घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक ढांचे को पुराने पड़ चुके संस्थानों के ज़रिए नहीं चलाया जाना चाहिए। उन्होंने नियम बनाने की प्रक्रिया में सुधार और ज़रूरी प्रतिनिधित्व की वकालत की। मोदी ने कहा कि हमारे विचारों की विविधता के साथ-साथ, ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज की चर्चा से यह साफ़ हो गया है कि बदलती दुनिया को पुराने पड़ चुके संस्थानों के ज़रिए नहीं चलाया जा सकता; प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम बनाने की प्रक्रिया में सुधार ज़रूरी हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों के विकास में 'ग्लोबल साउथ' की समान भागीदारी होनी चाहिए।

ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने की शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बातचीत, चीन के समर्थन पर जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत करते हुए, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के समय चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए उनका आभार जताया। शी के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'आपका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ब्रिक्स समिट में आपकी सकारात्मक बातों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।' उन्होंने आगे कहा, 'अब हमारे पास द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का मौका है। एक बार फिर, भारत में आपका गर्मजोशी से स्वागत है। राष्ट्रपति शी ने अपने संबोधन में कहा कि चीन और भारत एक-दूसरे की खूबियों से सीख सकते हैं और मिलकर विकास कर सकते हैं। उन्होंने दोनों देशों से ब्रिक्स सहयोग को और बेहतर बनाने और उच्च-गुणवत्ता वाले विकास के लिए साथ मिलकर काम करने का भी आग्रह किया।

भारी बारिश बनी आफत : मिजोरम में भूस्खलन, 14 साल के किशोर की मौत, चार घायल

नई दिल्ली, एजेंसी। मिजोरम के कोलासिब जिले में भारी बारिश के बाद शनिवार तड़के हुए भूस्खलन में 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। हादसा शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे वैरेंगटे कस्बे में हुआ, जो मिजोरम-असम सीमा के पास स्थित है। पुलिस के मुताबिक, मलबे में दबे किशोर का शव पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। मृतक की पहचान जोडिंगलियाना के रूप में हुई है। घायलों में से दो को इलाज के लिए पड़ोसी राज्य असम के सिलचर ले जाया गया, जबकि दो अन्य का उपचार वैरेंगटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, भूस्खलन से दो मकान और एक अन्य प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त मकानों में एक दो मंजिला लकड़ी का बना मकान था, जबकि दूसरा असम शैली का मकान था। इन इमारतों में तीन परिवार रहते थे, जिनमें कुल 17 लोग शामिल हैं। कोलासिब के पुलिस अधीक्षक लालरिनपुइया वारते ने बताया कि भूस्खलन भारी बारिश के कारण हुआ। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर नुकसान का आकलन कर रही हैं। फिलहाल किसी अन्य व्यक्ति के मलबे में दबे होने की सूचना नहीं है। मिजोरम में लगातार बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। वैरेंगटे राज्य का महत्वपूर्ण सीमावर्ती कस्बा है और असम के कछार जिले से सड़क संपर्क के लिहाज से भी अहम है।

'भारत की चुनाव प्रक्रिया सबसे पारदर्शी'

मतदाता सूची से मतगणना तक हर कदम पर पैनी नजर

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया दुनिया की सबसे पारदर्शी प्रणालियों में से एक है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची तैयार करने से लेकर वोटों की गिनती तक, हर एक कदम पर पूरी जांच-पड़ताल की जाती है। वह शुक्रवार को गुजरात यूनिवर्सिटी के अटल कलाम हॉल में आयोजित 'बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ संवाद' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में राजनीतिक दल, प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि लगातार निगरानी और सत्यापन का काम करते हैं। इसी वजह से हमारी चुनाव प्रक्रिया इतनी पारदर्शी है। मतदाता सूचियों की लगातार जांच में राजनीतिक दलों और उनके बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की भी पूरी भागीदारी होती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि बीएलओ की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वे अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत, दोहरे नाम और विदेशी (एएसडीडीएफ) मतदाताओं की पहचान करें। साथ ही वे यह सुनिश्चित करें कि हर पात्र व्यक्ति का नाम सूची में बना रहे। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हर पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में जरूर दर्ज होना चाहिए।

दिल्ली के 10 स्मारकों में ASI ने मरम्मत और संरक्षण कार्यों के चलते लगाई पर्यटकों पर रोक

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी में मरम्मत कार्यों की वजह से हौज खास किला, जंतर-मंतर और अग्रसेन की बावली जैसे स्मारकों में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत किये गए आवेदन के जवाब में दी गई है। 'पीटीआई-भाषा' को प्राप्त हुई जवाब की एक प्रति के मुताबिक दिल्ली में करीब 10 स्मारकों में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाई है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) वहां संरक्षण, मरम्मत और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आरटीआई के तहत दी गई जानकारी के मुताबिक हौज खास और कोटला फिरोज़ शाह परिसर में मौजूद स्मारकों के समूह में आपातकालीन ढांचागत मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि तुगलकाबाद किले और गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। आरटीआई के तहत दी गई जानकारी में कुतुब मीनार परिसर में सुलभता से जुड़े सुधारों के साथ-साथ सलीमगढ़ किले में सिग्नल रेजिमेंट बिल्डिंग और शौचालय खंड की संरचनात्मक मरम्मत और नवीनीकरण का भी जिक्र किया गया है। लाल किले के लाहौर गेट पर मौजूद मुंडेर समेत कुएं वाले इलाके के संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। आरटीआई के तहत प्राप्त जवाब के मुताबिक हौज खास-1 में इमारतों के एक समूह के कुछ हिस्से में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई है।

यूपी में 'सेवा दिवस' का महाभियान! एक महीने तक घर-घर पहुंचेगी डबल इंजन सरकार, तय हुए 11 बड़े कार्यक्रम

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा दिवस कार्यक्रम को लेकर कई जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेवा दिवस 17 सिंतबर से 17 अक्टूबर एक महीने चलेगा। इन कार्यक्रमों को लेकर अलग-अलग कार्ययोजना बनाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के 25 साल के कार्यकाल पूरा होने के रूप में उनके द्वारा किए गए योगदान की कृतज्ञता जताई। उन्होंने बताया कि कैसे पार्टी सेवा के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2026 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के अंदर और प्रधानमंत्री के रूप में देश के अंदर 25 वर्ष पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष की इस यात्रा का अभिनंदन करने की दृष्टि से राज्य सरकार और संगठन ने मिलकर कार्य योजना तैयार की है। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों को हम सब अवलोकन करते तो ये समग्र विकास की योजना और विजन प्रदान करता है। उन्होंने जिस भी क्षेत्र में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में योजना बनाई, उसमें विजन मिला। सीएम योगी ने कहा कि योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कैसे करना और लास्ट व्यक्ति तक कैसे उसकी पहुंच हो ये पूरे देश दुनिया ने बखूबी देखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो गुजरात को जहां सूखा सामना करना पड़ता था पेयजल का संकट था कनेक्टिविटी के इश्यू थे ढेर सारे चैलेंजेस थे उस गुजरात को लंबी परियोजना पूरा करके अंतिम गांव तक पेयजल की सुविधा से युक्त करके गुजरात को वेलफेयर स्टेट के रूप में बल्कि इंफ्रा के रूप में भी 13 साल के कालखंड के दौरान देश दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा उनकी जो यात्रा है नए भारत का दर्शन कराता है। इसने वर्ल्ड क्लास इंफ्रा दिया, वेलफेयर की स्कीम दी। टॉप 5 इकॉनमी में शामिल करने का मॉडल प्रस्तुत किया। भारत दुनिया के अंदर वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में G20 के अलग-अलग आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ब्रिक्स समिट नए भारत की दर्शाता है। सीएम योगी ने काह कि सोमनाथ मंदिर का विरोध तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया। राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाता है कि आपको इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए लेकिन उस सबके बावजूद राष्ट्रपति उस कार्यकम का हिस्सा बने। उनका काम भारत की विरासत को अपमानित करना है।

400 जवान जंतर-मंतर पर 9 अक्टूबर को करेंगे भूख हड़ताल, क्या साइबर ठगी का शिकार हुए 'ट्रेड्समैन'

नई दिल्ली, एजेंसी। सीमा सुरक्षा बल 'बीएसएफ' के 400 जवानों (ट्रेड्समैन) को एकाएक घर बैठा दिया गया है। नौकरी से निकाले जाने के बाद इन जवानों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। इन्हें नौकरी से हटाए जाने के पीछे मुख्य वजह एक नकली 'सर्टिफिकेट' है। भर्ती के समय अनेक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों के दावों पर भरोसा कर लिया। उन्हें 'सर्टिफिकेट' जारी कर दिया गया।

2023-24 के दौरान अभ्यर्थियों को इसी 'सर्टिफिकेट' पर नौकरी भी मिल गई। बाद में पता चला कि संबंधित संस्थान ने तो ऐसा कोई 'सर्टिफिकेट' जारी ही नहीं किया। इन जवानों को नौकरी पर रखा जाए, 'अलॉयंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन' ने सरकार से यह मांग की है। इसी के चलते एसोसिएशन ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 9 अक्टूबर को भूख हड़ताल करने की घोषणा की है।

महासचिव रणबीर सिंह ने क्या कहा?

'अलॉयंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने बताया, बीएसएफ में 2023-24 में रसोइया, जलवाहक (वाटर कैरियर) और वेटर के लिए रिक्तियां निकाली गई थी। जो विज्ञापन छपा, उसमें इन पदों के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत चलने वाले ट्रेनिंग सेंटर एनएसक्यूएफ से लेवल-1 सर्टिफिकेट होना अनिवार्य किया गया था। इस सर्टिफिकेट के बिना आवेदन नहीं किया जा सकता था। बाद में आरटीआई के जरिये पता चला कि एनएसडीसी ने 2015 से 2023 के बीच एनएसक्यूएफ लेवल-1 का कोई सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया।

नोएडा में गिरने की कगार पर 1757 इमारतें... 81 गांव में जर्जर मकानों को नोटिस, 2 हफ्ते में करना होगा खाली

>> नोएडा प्राधिकरण ने 81 गांव में सर्वे शुरू कराया >> जर्जर मकानों और भवनों की की जा रही है पहचान

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद नोएडा प्राधिकरण भी जर्जर और असुरक्षित भवनों को लेकर सक्रिय हो गया है। प्राधिकरण ने 81 गांव में ऐसे मकान और भवनों की पहचान के लिए सर्वे शुरू कराया है, जिनकी हालत रहने के लिहाज से खतरनाक है। सर्वे के दौरान चिन्हित भवनों पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। भवन मालिकों तथा वहां रहने वाले लोगों को मकान खाली करने के लिए एक से दो सप्ताह का समय दिया गया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन इमारत में सालों से रहने वाले लोगों क्या होगा और यह लोग ऐसे में अपने परिवार को लेकर जाएंगे कहां?

क्या प्राधिकरण इन्हें वैकल्पिक आवास देगा, किराए पर कहीं भेजेगा या सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराएगा? फिलहाल इन सवालों पर प्राधिकरण की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। अधिकारियों की ओर से इतना जरूर कहा गया है की जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद से भवन खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकता है।

यह पहली बार नहीं है कि जब नोएडा में जर्जर इमारतों की पहचान की जा रही है। वर्ष 2019 के सर्वे में करीब 1757 इमारतों को जर्जर या असुरक्षित चिह्नित किया गया था। इनमें 56 भवन जर्जर और असुरक्षित बताए गए थे, जबकि 1326 इमारतें 3 साल से अधिक की थीं। 114 बहू मंजिलें इमारतें अनुसूची और अर्जित क्षेत्र में थीं तथा 114 ऐसी इमारतें थी, जो ध्वस्तीकरण के आदेश के बावजूद भी यह खड़ी रहीं।

उस समय कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण ने फिर से सर्वे और नोटिस की कार्रवाई तेज कर दी है। नोएडा प्राधिकरण को 10 वर्क सर्कल में बांटा गया है और उनके अंतर्गत 81 गांव आते हैं। सभी सर्कल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में जर्जर भवनों की पहचान को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है।

इन इलाकों में हैं सबसे ज्यादा ऊंची इमारतें

सदरपुर, निठारी, मामूरा, सलारपुर और भंगेल जैसी घनी आबादी वाले गांव में सर्वे चल रहा है, क्योंकि यह वही इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने किराए के लिए ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की हैं। मामूरा में अब तक 9 भवनों पर जर्जर होने का नोटिस चस्पा किया जा चुका है, जबकि इनमें अभी भी लोग रह रहे हैं। गांव के अलावा सेक्टर 31 के 128 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को भी जर्जर स्थिति के कारण नोटिस जारी किए गए हैं। प्राधिकरण का कहना है की खतरनाक भवनों को खाली कराया जाएगा, ताकि किसी भी दुर्घटना में जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन जिन परिवारों के पास दूसरा घर नहीं है, उनके लिए दो सप्ताह में घर खाली करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अब कार्रवाई के साथ-साथ पुनर्वास और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

मकान खाली करने से पहले इस सवाल का जवाब जरूरी

लोगों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जर्जर मकान खाली करने से पहले यह बताना उतना ही जरूरी है कि इन परिवारों को सुरक्षित छत आखिर मिलेगी कहां? बता दें किसत्य निकेतन में 6 सितंबर को 5 मंजिला इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद देश भर में पुराने और असुरक्षित भवनों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं।

जनपदीय प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं की मेधा का लहराया परचम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में आयोजित जनपद स्तरीय वाद-विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता में छात्रों ने मनवाया अपने ज्ञान का लोहा । नगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित श्लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सीमा विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसका शुभारंभ शिक्षा विभाग के मुखिया जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्य प्रकाश सिंह, सह जिला विद्यालय निरीक्षक जटाशंकर यादव एवं जीआईसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। सफल कार्यक्रम का कुशल संयोजन शिक्षक केशव प्रसाद सिंह एवं सुनील यादव जी ने किया। कार्यक्रम में तकनीक का बेहतरीन प्रयोग करते हुए पीपीटी के माध्यम से स्क्रीन पर प्रसारण भी किया गया। इस अवसर पर जिला विद्या निरीक्षक ने ज्ञान को तकनीक से जोड़ने के प्रयासों एवं उसके प्रस्तुतीकरण की प्रशंसा की । उन्होंने ऐसे आयोजनों के सातत्य पर बल दिया । सन्तोष मिश्र, पीईएस (प्रधानाचार्य) ने छात्र-छात्राओं की उनकी समर्थ प्रस्तुति के लिए सराहना की। विजयी प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के पश्चात डॉ मनोज कुमार तिवारी (पीईएस) ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में पच्चीस राजकीय विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल में प्रो०(डा) अश्वनी सिंह (गनपत सहाय), दीपक कुमार सिंह (एम जी एस), सूर्यभान (प्रधानाचार्य) रहे। आयोजन को सफल बनाने में राजकीय इंटर कॉलेज सुल्तानपुर के डॉक्टर पंकज सिंह गायत्री प्रसाद तिवारी ममता सिंह, स्वाति, संजय कुमार, शिव शंकर, हेमंत सिंह, भूपेश यादव, राय साहब यादव की सराहनीय भूमिका रही।

राष्ट्रीय लोक अदालत में लगा नि :शुल्क स्वास्थ्य शिविर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जनपद न्यायालय सुल्तानपुर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में न्यायालय परिसर पहुंचे वादकारियों, अधिवक्ताओं एवं न्यायालय कर्मचारियों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया।

शिविर का जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ, सचिव मुक्ता त्यागी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी भारत भूषण ने निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत कुल 349 लोगों की जांच की। शिविर में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 68 लोगों की एक्स-रे जांच, मलेरियाध/फाइलेरिया कार्यक्रम में 25, राष्ट्रीय अंधता

निवारण कार्यक्रम के तहत 24, एनसीडी के अंतर्गत 84 लोगों की शुगर तथा 108 लोगों की बीपी जांच की गई। वहीं 12 लोगों को आयुष्मान योजना से संबंधित सेवाएं दी गईं तथा 28 लोगों की ईसीजी जांच हुई। शिविर में चिकित्साधिकारी डॉ. इमरान युसुफ, डॉ. आयुषी, डॉ. देवाशीष, जूनियर रेजिडेंट डॉ. संजीत पाठक, डेंटल सर्जन डॉ. विमल प्रकाश सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर के संचालन में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूबेपुर, कादीपुर, बल्दीराय, राजकीय टीबी क्लीनिक तथा कार्यालय मलेरिया अधिकारी की टीम ने सहयोग किया।

बिजनौर पहुंची यूपी विधानसभा की कमेटी...

रावली तटबंध और जिला अस्पताल का लिया जायजा

आर्यावर्त संवाददाता

बिजनौर। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति ने शुक्रवार को बिजनौर जिले का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी संस्थानों का सघन निरीक्षण किया। समिति के संयोजक व संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद के नेतृत्व में पहुंची इस टीम में राम खिलाड़ी सिंह यादव, राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार प्रजापति शामिल रहे। जांच दल ने गंगा नदी के रावली तटबंध, धर्मनगरी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और जिला अस्पताल (मेडिकल कॉलेज) का जायजा लिया।

विकास कार्यों की समीक्षा के बाद समिति के अध्यक्ष इकबाल महमूद ने स्थानीय प्रशासन के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। समिति ने सबसे पहले गंगा नदी के लेफ्ट अफ्लैक्स बंध (रावली तटबंध) पर पहुंचकर वहां किए गए बाढ़ सुरक्षा कार्यों की बारीकी से जांच की। मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता कर्ण पाल सिंह ने समिति को बताया कि इस बेहद संवेदनशील तटबंध की सुरक्षा के लिए 35 करोड़ रुपये की लागत का बड़ा प्रोजेक्ट सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

इस परियोजना में आधुनिक तकनीक 'स्पेशल एसीबीएम' का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कार्य करने वाली फर्म को अब तक 9 करोड़ 25 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। खास बात यह है कि यही फर्म अगले पांच वर्षों तक इस तटबंध के मेंटेनेंस (रखरखाव) की जिम्मेदारी भी संभालेगी। कार्य की उच्च गुणवत्ता को देखकर विधानसभा समिति के सदस्यों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जमकर तारीफ की और उनकी पीठ थपथपाई। इसके बाद समिति के सदस्य धर्मनगरी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास विद्यालय पहुंचे। यहां समिति के विधायकों ने स्कूल की व्यवस्थाओं को देखा और वहां पढ़ाई कर रही छात्राओं से सीधा संवाद किया। निरीक्षण के दौरान सदस्यों ने छात्राओं से गणित के पहाड़े भी सुने, जिसका बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ सही जवाब दिया। स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई और छात्राओं के खान-पान से समिति बेहद संतुष्ट नजर आई।

जिला अस्पताल का निरीक्षण

विधायकों ने बच्चियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें जीवन में बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से मेहनत करने की प्रेरणा दी। बेड की चादरें रोज बदलने के सख्त निर्देश दौरे के अंतिम चरण में आश्वासन समिति ने जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायकों ने इमरजेंसी, ओपीडी, विभिन्न वार्डों, रसोईघर (किचन) और डिस्पेंसरी (दवा वितरण केंद्र) की व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान विधायकों ने इमरजेंसी, ओपीडी, विभिन्न वार्डों, रसोईघर (किचन) और डिस्पेंसरी (दवा वितरण केंद्र) की व्यवस्थाओं को परखा। समिति ने डॉक्टरों की उपस्थिति और दवाओं की उपलब्धता की भी जानकारी ली। मरीजों की सहूलियत को देखते हुए समिति सदस्यों ने अस्पताल प्रशासन को कड़े निर्देश दिए कि भर्ती मरीजों के बेड की चादरें हर दिन अनिवार्य रूप से बदली जाएं। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी गई।

प्रशासन के कार्यों से समिति संतुष्ट

निरीक्षण कार्यक्रम के समापन पर समिति के अध्यक्ष इकबाल महमूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "बिजनौर में स्थानीय प्रशासन ने विकास कार्यों को लेकर बहुत ही बढ़िया काम कराया है। हमारी समिति यहां कराए गए विकास कार्यों और व्यवस्थाओं की जांच से पूरी तरह संतुष्ट है।" इस निरीक्षण के दौरान जिले की डीएम जसजीत कौर, एसडीएम स्मृति मिश्रा, एसपी केके विश्नोई, एक्सीएन सिचाई विभाग कर्णपाल सिंह, सीएमओ, सहित तमाम आला अधिकारी और संबंधित विभागों के अभियंता भी मौजूद रहे।

बेटे के सामने अवैध संबंधों का राज खुला तो... मां ने जान से मार डाला, अगले दिन प्रेमी ने भी की सुसाइड की कोशिश

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद खौफनाक और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। 14 वर्षीय किशोर को अपनी मां और पड़ोस के युवक को आपत्तिजनक स्थिति में देखना भारी पड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही मासूम बेटे का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मां रात भर बेटे की लाश के पास बैठकर पूरी घटना को छुपाती रही।

घटना गुरुवार रात की है। शुक्रवार की सुबह आरोपी महिला ने आसपास के लोगों और पड़ोसियों के बीच यह अफवाह फैला दी कि उसके 14 साल के बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। हालांकि, गांव में महिला के अवैध संबंधों और हत्या की चर्चाएं तेज हो गईं। शंका होने पर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस

कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दे दी।

सूचना मिलते ही महाराजपुर थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान किशोर की गर्दन और शरीर पर चोट के संदिग्ध निशान मिले, जिससे मामला सामान्य मौत का नहीं लगा। पुलिस ने शव को तुरंत कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

पोस्टमार्टम में गला घोंटने की पुष्टि, पिता करते हैं मुंबई में काम

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पुलिस के दावों की पुष्टि हो गई। रिपोर्ट में साफ हुआ कि किशोर की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि सांस नली (गला) दबाने से हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक किशोर के पिता मुंबई में शटरिंग का काम करते हैं और घर का खर्च चलाते हैं। घर पर उनकी पत्नी और तीन बेटे रहते थे। ग्रामीणों के अनुसार, महिला का पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। गुरुवार रात बेटे ने दोनों को साथ देख लिया था, जिसके बाद यह खौफनाक वारदात घटी।

राज खुलने के डर से प्रेमी ने की खुदकुशी की कोशिश, तलाश में जुटी पुलिस

इधर, जब गांव में हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा और पुलिस की जांच तेज हुई, तो आरोपी प्रेमी को अपने गिरफ्तार होने का डर सताने लगा। घबराहट में उसने अपने ही घर में फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। हालांकि, ऐन वक्त पर परिजनों और पड़ोसियों की नजर पड़ गई और उन्होंने शोर मचाते हुए उसे फंदे से नीचे उतार लिया। इसके तुरंत बाद आरोपी युवक मौका पाकर गांव से फरार हो गया। कानपुर पुलिस का कहना है कि हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपी मां से पूछताछ की जा रही है और फरार प्रेमी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।

41 टन चोरी गई सरिया बरामद, 02 गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। असम से सरिया लेकर लखनऊ जा रहा ट्रक कूरेभार थाना क्षेत्र से गायब होने के बाद यश ट्रेडर्स लखनऊ के फर्म संचालक के रिश्तेदार ने 09 सितम्बर को कूरेभार पुलिस को तहरीर देकर ट्रेलर वाहन के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 04 आरोपियों में 02 को चोरी गई सरिया, ट्रेलर व ट्रक के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। शनिवार को सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने चोरी गई सरिया का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि लखनऊ निवासी अमित कुमार सिंघनिया जो यश ट्रेडर्स के मालिक है उनके रिश्तेदार निमेंद्र गोयल निवासी पलटन बाजार थाना कोतवाली नगर ने 09 सितम्बर को कूरेभार पुलिस को तहरीर देकर असम से लखनऊ जा रही सरिया की कूरेभार थाना क्षेत्र से चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराई थी।मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने के मामले में अभय मिश्रा पुत्र अखिलेश मिश्रा निवासी सराय कल्याण कादीपुर, चंदन गौतम पुत्र राम आधार गौतम निवासी सोनावा चांदा, जयदीप यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासी लालू का पुरवा सोनावा चांदा व सौरभ पुत्र चंद्र भूषण द्विवेदी निवासी विनोबापुरी कोतवाली नगर की शिनाख्त की। शनिवार को कूरेभार पुलिस ने अखिलेश मिश्रा व चंदन गौतम को थाना क्षेत्र के एनपुर नहर के पास से गिरफ्तार किया जिनसे पुलिस ने 41 टन सरिया कीमत लगभग 19 लाख,एक ट्रक सरिया लदी हुई व खाली ट्रेलर जिससे असम से सरिया निकली थी उसे बरामद किया। गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष उपेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक राजेश कुमार, दीवान दयानंद यादव, आरक्षी उमेश यादव, अरुण यादव, सुनील यादव शामिल रहे।

शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रहा है एमजीएस इंटर कॉलेज : डॉ . विनोद सिंह

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में शनिवार को परिचयात्मक एवं शिक्षा उन्नयन गोष्ठी का अत्यंत गरिमामयी माहौल में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षत्रिय शिक्षा समिति के अध्यक्ष ठाकुर संजय सिंह, विद्यालय के प्रबंधक व उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के सदस्य डॉ. विनोद सिंह एवं प्रबंध समिति के पदाधिकारियों द्वारा बाबू बेचू सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन व पुष्पार्चन के साथ हुआ। परिचयात्मक सत्र के दौरान नवनिर्वाचित प्रबंध समिति के समक्ष विद्यालय के कर्मठ शिक्षकों ने अपना परिचय दिया। इसके उपरांत संस्थान के शैक्षणिक स्तर को नए शिखर पर ले जाने के लिए डॉ. अजय कुमार सिंह, मधुलिका सिंह, सुमित कुमार, बलराम सिंह, डॉ. विशाल सिंह, अशोक सिंह और मारुत नंदन आदि शिक्षकों ने अपने नवाचारी विचार और ठोस सुझाव साझा किए। प्रबंध समिति ने शिक्षकों के इन सुझावों की सराहना करते हुए उनका मार्गदर्शन किया।

शिक्षकों के विचारों पर अपनी मुहर लगाते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य व प्रबंधक डॉ. विनोद सिंह ने कहा, ष्हमारा संस्थान अनुशासित वातावरण में उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे शिक्षक उच्च कोटि की योग्यता रखते हैं, जिसका प्रमाण हमारे इंग्लिश मीडियम विंग का शत-प्रतिशत (100:) परीक्षा परिणाम है। डॉ. सिंह ने एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा करते हुए कहा कि जहाँ आज जनपद के अन्य सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या में गिरावट देखी जा रही है, वहीं हमारे विद्यालय में छात्र संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह जनता के अटूट विश्वास, उत्तम अनुशासन और हमारे उत्कृष्ट शैक्षणिक माहौल की पुष्टि करता है। क्षत्रिय शिक्षा समिति के अध्यक्ष ठाकुर संजय सिंह ने छात्र-छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए एक प्रेरक घोषणा की। उन्होंने कहा, ष्जिस दिन हमारे विद्यालय का कोई भी होनहार छात्र प्रदेश स्तर की मेरिट सूची में स्थान बनाएगा, उस दिन प्रबंध समिति द्वारा उसका ऐतिहासिक और भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में यहाँ के विद्यार्थी इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने गर्व से रेखांकित किया कि डळै जनपद का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो बालिकाओं को पूरी तरह निशुल्क गणवेश (यूनिफॉर्म) प्रदान कर महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। कार्यक्रम का संचालन विचित्र वीर सिंह ने किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रधानाचार्य महेश कुमार सिंह ने आए हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने पूरी प्रबंध समिति को आश्वस्त किया कि गोष्ठी में आए सभी बहुमूल्य सुझावों को विद्यालय की कार्यप्रणाली में पूरी तरह लागू किया जाएगा और संस्थान में उच्च स्तरीय शैक्षणिक वातावरण को निरंतर अक्षुण्ण रखा जाएगा।

ब्रिक्स समिट में विदेशी मेहमानों को पिलाई जा रही बिजनौर की चाय

ब्रिक्स सम्मेलन में विदेशी मेहमानों को पिलाई जा रही बिजनौर की चाय

आर्यावर्त संवाददाता

बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के छोटे से गांव लखीवाला की ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही 'विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी' ने आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहरा दिया है। दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन में आए दुनिया भर के शीर्ष नेताओं और विदेशी मेहमानों को इस स्वदेशी ऑर्गेनिक हर्बल चाय का जायका परोसा जा रहा है, जिसकी विदेशी कूटनीतिज्ञ और मेहमान जमकर तारीफ कर रहे हैं।

कभी महज 1 लाख रुपये के छोटे से लोन से शुरू हुआ यह सफर आज 12 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाले विशाल ग्लोबल ब्रांड में तब्दील हो चुका है। दिल्ली में चल रहे BRICS सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों और अधिकारियों के लिए 'विदुर हर्बल टी' आकर्षण का मुख्य

केंद्र बनी हुई है।

इस ऑर्गेनिक चाय की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता को देखते हुए अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि सात समंदर पार अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे विकसित देशों में इसकी फ्रेंचाइजी और आउटलेट खोलने की जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल और प्रयागराज के महाकुंभ में भी अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों ने इस स्वदेशी चाय की चुस्कियों की खूब सराहना की थी।

लोकल से ग्लोबलः 1 लाख रुपये से 12 करोड़ का साम्राज्य

बिजनौर जिला प्रशासन द्वारा दिसंबर 2023 में स्थापित इस कम्युनिटी ब्रांड की नींव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत रखी गई थी। स्वयं सहायता समूह की बबीता रानी और उनकी साथी महिलाओं ने मिलकर एक छोटे से प्रयास के रूप में इसकी शुरुआत की थी। आज बिजनौर में ही इसके 35 से अधिक आउटलेट और कैफे संचालित हो रहे हैं, जबकि मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में इसका नेटवर्क तेजी से फैल रहा है।

सेहत का खजाना है यह प्राकृतिक हर्बल चाय

विदुर हर्बल टी को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान का सबसे बड़ा कारण इसकी शत-प्रतिशत शुद्धता और आयुर्वेदिक गुण हैं। यह पूरी तरह से प्राकृतिक और स्वदेशी जड़ी-बूटियों का मिश्रण है, जिसमें शामिल हैं-

लेमन ग्रास और तुलसीः ताजगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए।

गिलोय और कच्ची हल्दीः शरीर को संक्रमण, सर्दी-खांसी और वायरल से बचाने के लिए।

मुलेठी और दालचीनीः गले की खराश दूर करने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए।

इलायची और सौंफः बेहतरीन प्राकृतिक स्वाद और सुगंध के लिए।

पीएम नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में की सराहना

बिजनौर की इन हुनरमंद महिलाओं की सफलता की गूंज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंची। पीएम मोदी ने अपने प्रसिद्ध कार्यक्रम 'मन की बात' के 136वें एपिसोड में बिजनौर की इन महिलाओं के प्रयास की खुले दिल से तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कहा था, "जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास एक साथ मिलता है, तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है।" पीएम की इस प्रेरणादायक सराहना के बाद से विदुर चाय के वैश्विक ऑर्डर्स और डिस्ट्रीब्यूटरशिप की मांग में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई।

300 से अधिक महिलाएं बनीं 'लखपति दीदी'

बिजनौर की जिलाधिकारी (DM) जसजीत कौर ने बताया कि विदुर ब्रांड आज उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। इस मुहिम के माध्यम से बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों की 300 से अधिक ग्रामीण महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं और सैकड़ों अन्य परिवारों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। कभी घर के चूल्हे-चौके तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने उत्पाद का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और विदेशी एक्सपोर्ट डील संभाल रही हैं।

प्रधानाचार्य शिक्षा व्यवस्था की रीढ़, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में निभाएं अहम भूमिका: केशव प्रसाद मौर्य

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेशीय सम्मेलन एवं शैक्षिक उन्नयन विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को नई दिशा देने में प्रधानाचार्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य केवल विद्यालय के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करते, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य वर्तमान पीढ़ी को ऐसी शिक्षा, दीक्षा और संस्कार प्रदान करते हैं, जिससे भारत और उत्तर प्रदेश भविष्य में हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ सकें। प्रदेशभर से सम्मेलन में पहुंचे प्रधानाचार्यों का स्वागत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा जगत के इन महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों का अनुभव और मार्गदर्शन प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने में उपयोगी है।केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में शिक्षा सहित प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास के कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा के विस्तार, नवाचार को प्रोत्साहन तथा विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सामने आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हाल ही में विधान परिषद में शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र के सदस्यों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ हुई विस्तृत बैठक में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकों से शिक्षा व्यवस्था की जमीनी समस्याओं को समझने और उनके समाधान का रास्ता निकालने में मदद मिलती है।उप मुख्यमंत्री ने प्रधानाचार्य परिषद की ओर से रखी गई समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानाचार्यों के सम्मान और उनकी गरिमा से जुड़े विषयों को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति के चयनित होकर आने पर पूर्व प्रधानाचार्य को उसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करना पड़े तो इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचने की स्थिति बन सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस विषय में शासन स्तर पर आवश्यक प्रयास किए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी चर्चा की जाएगी।उन्होंने कहा कि विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था से जुड़े विषयों सहित परिषद के ज्ञापन में उल्लिखित अन्य समस्याओं पर भी संबंधित स्तर पर चर्चा कर समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षकों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा संबंधी सुविधाओं से शिक्षक वर्ग को राहत मिली है। इसी प्रकार प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से सहायता प्राप्त विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से मिलने वाला जमीनी फीडबैक सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसके भविष्य के निर्माण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आत्मनिर्भरता, नवाचार और संस्कारयुक्त शिक्षा को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने प्रधानाचार्यों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें संस्कार, अनुशासन, राष्ट्रभाव और जिम्मेदारी का बोध कराते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें।

लखनऊ मंडल में डिजिटल सुविधा का विस्तार, अब 24 घंटे उपलब्ध होंगे स्नैक्स और पेय पदार्थ

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। यात्रियों और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और परिसरों में स्वचालित वेंडिंग मशीन 'लखन खजाना' स्थापित की जा रही हैं। इसी क्रम में बंदरियाबाग स्थित 'संस्कृति' ऑफिसर्स क्लब में भी स्वचालित वेंडिंग मशीन 'लखन खजाना' स्थापित की गई है। इस मशीन के माध्यम से रेलवे कॉलोनी, ऑफिसर्स क्लब और आसपास के लोगों को अब स्नैक्स तथा पेय पदार्थ चौबीसों घंटे आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन स्वचालित वेंडिंग मशीनों को तैयार किया गया है। मशीनों में यूपीआई के माध्यम से नकदी रहित भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। जिस प्रकार एटीएम के माध्यम से आसानी से लेनदेन किया जाता है, उसी प्रकार इन मशीनों के माध्यम से भी लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद्य एवं पेय पदार्थ खरीद सकेंगे। डिजिटल भुगतान की सुविधा होने से लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी और नकदी रखने की आवश्यकता भी कम होगी।उन्होंने कहा कि रेलवे परिसरों में इस प्रकार की स्वचालित व्यवस्था शुरू करना बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप यात्रियों और आम लोगों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 'लखन खजाना' मशीनें विशेष रूप से उन स्थानों पर उपयोगी साबित होंगी, जहां लोगों को देर रात या दिन के किसी भी समय स्नैक्स और पेय पदार्थ की आवश्यकता होती है।

गोरखपुर राजघाट निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, अखिलेश ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर के राजघाट निर्माण को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजघाट के निर्माण के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि जारी की गई थी, लेकिन सिंचाई विभाग ने भाजपाइयों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की ऐसी नहर निकाल ली, जिसमें स्वार्थ के कई खेत सींचे गए। यही वजह है कि निर्माण की स्थिति बदहाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में हुई कमीशनखोरी के कारण ही दो अधिवक्ताओं की असामयिक जान चली गई। अखिलेश यादव ने कहा कि निर्माण की दुर्गति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से की जा रही असंवेदनशील बयानबाजी मृतकों के परिजनों के घाव पर नमक छिड़कने जैसी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारियों को इस तरह की भाषा बोलने और असंवेदनशील बयान देने का साहस कहां से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे भ्रष्ट अधिकारियों को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण को समझना मुश्किल नहीं है।सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार मृतकों और पीड़ित परिवारों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि जनता अब उनके भाषण और बयान सुनने के मूड में नहीं है। उन्होंने मांग की कि निर्माण कार्य में संलिप्त अधिकारियों और गैरजिम्मेदाराना बयान देने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। यदि उनका निलंबन नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि वे अपने मुखिया और सांसद के कहने पर भ्रष्ट कार्य और गैरजिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं।उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि स्थिति इतनी खराब है कि यदि लोगों को पता चल जाए कि कोई निर्माण भाजपा शासनकाल में हुआ है तो लोग उस निर्माण की मजबूती पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में निर्मित छतरी और द्वार के नीचे लोग खड़े होने से डरेंगे, पानी की टंकी देखकर दूर भागेंगे, दीवार का सहारा लेने से बचेंगे और भाजपा शासनकाल में बनी सड़क, राजमार्ग तथा द्रुतगति मार्ग पर चलने से भी डरेंगे। उन्होंने कहा कि पुलों से गुजरने और मंदिर तथा संसद की टपकती छतों को देखकर भी लोगों में भय पैदा हो रहा है।अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने भ्रष्टाचार का वैश्विक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को यह भी नहीं लगता कि घटिया और जानलेवा निर्माण कभी उनके अपने लोगों और परिवारों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

गोंडा जा रहे अजय राय समेत कांग्रेसजनों को पुलिस ने रोका, मसौली थाने में हिरासत के खिलाफ धरना

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। जनपद गोंडा के करनैलगंज क्षेत्र के रेक्सड़िया निवासी बर्तन कारोबारी स्वर्गीय विनोद साहनी की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने और शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह सहित दर्जनों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाराबंकी टोल प्लाजा के पास भारी पुलिस बल ने रोककर हिरासत में ले लिया। पुलिस सभी को मसौली थाने ले गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मसौली थाने पहुंचने लगे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही राजमार्ग पर रोक दिया। इसके बाद थाने पर पहुंचे सैकड़ों कांग्रेसजनों ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना-प्रदर्शन किया।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसी पीड़ित परिवार के घर जाकर संवेदना व्यक्त करना अपराध है। उन्होंने पूछा कि उन्हें किसके आदेश पर रोका गया और यदि ऊपर से आदेश दिया गया था तो उसे दिखाया क्यों नहीं गया। क्या पुलिस को बिना लिखित आदेश के इस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों के बीच गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और व्यापारी वर्ग के पीड़ित परिवारों के घर जाकर उनके दुख-दर्द में शामिल होने पर सरकार भयभीत क्यों हो जाती है।अजय राय ने आरोप लगाया कि योगी सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कांग्रेस नेताओं को पीड़ितों से मिलने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को उन्हें रोकने के बजाय अपराध रोकने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी के सिपाही हैं और कांग्रेस का स्पष्ट मंत्र है कि जहां कहीं पीड़ा होगी, वहां कांग्रेस के नेता दिखाई देंगे। कांग्रेस न तो डरेगी और न ही सत्ता की कथित तानाशाही के सामने झुकेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़े वर्ग के निषाद समुदाय से जुड़े बर्तन कारोबारी विनोद साहनी की जिस तरह गोली मारकर हत्या की गई, वह बेहद दुखद और गंभीर घटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही हत्या, दुष्कर्म और लूट की घटनाएं सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों को सरकार का वैचारिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण उनका मनोबल बढ़ रहा है और प्रदेश में जंगलराज जैसी स्थिति पैदा हो गई है।अजय राय ने यह भी कहा कि अपनी सरकार की इज्जत बचाने के लिए योगी सरकार के मंत्री विपक्ष के धरने में शामिल होकर कार्रवाई की मांग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को विपक्ष के धरने में शामिल होने के बजाय सरकार पर दबाव बनाकर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

ग्रीन गैस के नाम पर साइबर ठगी से सावधान, संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड कराना अपराधियों का नया तरीका

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ पुलिस की अपराध शाखा ने ग्रीन गैस के नाम पर आमजन के साथ किए जा रहे नए साइबर ठगी के प्रयासों को लेकर लोगों को सतर्क किया है। साइबर अपराधियों द्वारा ग्रीन गैस के नाम का दुरुपयोग करते हुए वाट्सऐप संदेश, एसएमएस और फोन कॉल के माध्यम से उपभोक्ताओं से संपर्क किया जा रहा है। अपराधी बिल अपडेट करने, मीटर या ग्राहक पहचान सत्यापन, गैस कनेक्शन अपडेट करने अथवा अन्य किसी बहाने से मोबाइल पर संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड और स्थापित करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।पुलिस के अनुसार, ऐसी संदिग्ध एपीके फाइल मोबाइल में स्थापित करने से साइबर अपराधियों को मोबाइल की संवेदनशील जानकारी और गतिविधियों तक अनधिकृत पहुंच मिल सकती है। इसके माध्यम से एक बार इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड, संदेश, बैंकिंग संबंधी जानकारी और अन्य निजी आंकड़ों का दुरुपयोग कर आर्थिक धोखाधड़ी की जा सकती है। अपराधी लोगों को डराने के लिए यह संदेश भी भेज रहे हैं कि बिल अपडेट नहीं होने के कारण रात साढ़े आठ बजे तक उनका पाइप गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा और तत्काल दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने या बिल अपडेट करने को कहा जा रहा है।लखनऊ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी एपीके फाइल केवल डाउनलोड की है और उसे स्थापित नहीं किया है, तो उसे खोलने या स्थापित करने के बजाय तत्काल हटा देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने गलती से एपीके फाइल स्थापित कर ली है तो घबराने के बजाय मोबाइल को तत्काल इंटरनेट से अलग कर देना चाहिए। इसके लिए वाई-फाई और मोबाइल इंटरनेट बंद करने, संदिग्ध अनुप्रयोगों को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अनुमति नहीं देने और साइबर स्वच्छता केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट से उपलब्ध सुरक्षा उपकरण के माध्यम से मोबाइल की पूरी जांच कराने की सलाह दी गई है। पुलिस ने महत्वपूर्ण पासवर्ड और अन्य गोपनीय जानकारी को संभव हो तो किसी दूसरे सुरक्षित उपकरण से बदलने तथा बैंक खाते, यूपीआई और अन्य वित्तीय लेनदेन की तत्काल जांच करने को कहा है।यदि किसी व्यक्ति के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो चुकी है तो उसे तत्काल 1930 पर संपर्क करने और साइबर अपराध की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। पुलिस ने कहा है कि जिस मोबाइल नंबर से संदिग्ध एपीके फाइल या वाट्सऐप संदेश प्राप्त हुआ है, उसे सुरक्षित रखना बेहद महत्वपूर्ण है। संदिग्ध संदेश को हटाने के बजाय उसका पूरा विवरण और स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें तथा संदेश भेजने वाले मोबाइल नंबर सहित लखनऊ पुलिस की अपराध शाखा की संगठित अपराध हेल्पलाइन 7839861034 पर अग्रेषित करें।अपर पुलिस उपायुक्त अपराध, लखनऊ किरन यादव ने कहा कि लखनऊ अपराध शाखा लगातार आमजन को इस नए साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रही है। आमजन द्वारा उपलब्ध कराया गया संदिग्ध मोबाइल नंबर और वाट्सऐप संदेश साइबर अपराधियों की पहचान करने और उनके नेटवर्क तक पहुंचने में महत्वपूर्ण सुराग साबित हो सकता है।

नई व्यवस्था में संबंधित इकाइयां ही निस्तारित करेंगी बिजली विभाग के पेंशनरों के प्रकरण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने नई वर्टिकल व्यवस्था में पेंशनरों के पेंशन संबंधी प्रकरणों के निस्तारण को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी विद्युत वितरण निगमों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कारपोरेशन ने कहा है कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा चिकित्सा भत्ते के भुगतान से संबंधित कार्य अब पेंशनर की संबंधित खंड अथवा इकाई के नामित अधिकारी के स्तर से ही निस्तारित किए जाएंगे। कारपोरेशन के निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन डॉ. जॉन मथाई की ओर से 11 सितंबर को जारी पत्र में पूर्व में 27 जनवरी 2026 को जारी निर्देशों का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि जिन वितरण निगमों में नई वर्टिकल व्यवस्था प्रभावी हो चुकी है।

संक्षेप

काकोरी में युवक ने फांसी लगाकर जान दी, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

लखनऊ। काकोरी थाना क्षेत्र के ग्राम मौदा में शनिवार को 33 वर्षीय युवक ने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर काकोरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की।पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान ग्राम मौदा निवासी अनुराग पांडे उर्फ संजू पांडे पुत्र राजकुमार पांडे के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर क्षेत्रीय जांच दल को बुलाया। टीम ने घटनास्थल और शव की वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई। परिजनों की मौजूदगी में पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।पुलिस ने बताया कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बाइक की टक्कर के बाद विवाद में चाकू से हमला, बुजुर्ग की मौत, पौत्र घायल

लखनऊ। मड़ियांव थाना क्षेत्र में शनिवार को बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद में एक व्यक्ति ने बुजुर्ग और उनके पौत्र पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उनके पौत्र का ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है। घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।पुलिस के अनुसार 70 वर्षीय मदन बिहारी तिवारी अपने 19 वर्षीय पौत्र संकल्प तिवारी के साथ बाइक से सीतापुर रोड पर जा रहे थे। कृष्ण लोक कॉलोनी के सामने देशी शराब के ठेके के पास उनकी बाइक एक व्यक्ति की बाइक से टकरा गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने चाकू निकालकर मदन बिहारी तिवारी और उनके पौत्र संकल्प तिवारी पर हमला कर दिया। चाकू के हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

लखनऊ पुलिसकर्मियों को ट्रांसजेंडर अधिकारों और पशु क्रूरता निवारण कानून का प्रशिक्षण

लखनऊ। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के निर्देशन में शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित संगोष्ठी सदन में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों, पुलिस संवेदीकरण तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 के संबंध में प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और उनके प्रति संवेदनशील पुलिसिंग के लिए जागरूक करने के साथ ही पशु क्रूरता से जुड़े मामलों में प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्रवाई के प्रति उनकी जानकारी और दक्षता बढ़ाना रहा।कार्यशाला में उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की राज्य कार्यकारी सदस्य एवं सलाहकार देविका देवेन्द्र एस मंगलामुखी ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 और नियमावली-2020 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी पुलिसकर्मियों को दी।

95 प्रशिक्षु पीसीएस अधिकारियों ने लखनऊ की कचरा और सीवेज प्रबंधन व्यवस्था का किया स्थलीय अध्ययन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। 91वें आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार को 95 प्रशिक्षु पीसीएस अधिकारियों के दल ने लखनऊ नगर निगम की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थलीय अध्ययन किया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिवरी स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, भैंसौरा स्थित फिक्स्ड कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन और भरवारा स्थित सीवेज शोधन संयंत्र का दौरा कर वहां संचालित व्यवस्थाओं, तकनीकों और कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की।प्रशिक्षु अधिकारियों के दल ने सबसे पहले शिवरी स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने लखनऊ नगर निगम द्वारा ठोस कचरे के प्रबंधन, उसके निस्तारण तथा कचरे से उपयोगी उत्पाद तैयार करने के लिए अपनाई जा रही व्यवस्थाओं को करीब से समझा। अधिकारियों को लखनऊ को 'शून्य कचरा शहर' बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। कचरे से निकलने वाले विभिन्न उत्पादों के उपयोग तथा नारियल गड्ढा मॉडल के बारे में भी अधिकारियों को विस्तार से बताया गया।शिवरी संयंत्र पहुंचने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को दो समूहों में विभाजित किया गया था। ग्रुप 'सी' में 47 तथा ग्रुप 'डी' में 48 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल रहे। दोनों समूहों ने संयंत्र में कचरा प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों से कार्यप्रणाली तथा तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी ली। प्रशिक्षु अधिकारियों ने कचरे के संग्रह से लेकर उसके प्रसंस्करण और उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया को समझने में विशेष रुचि दिखाईइसके बाद प्रशिक्षु अधिकारियों ने भैंसौरा स्थित फिक्स्ड कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया। यहां उन्हें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए जाने वाले कचरे को कॉम्पेक्टर के माध्यम से दबाकर कम स्थान में एकत्र करने तथा उसके बाद आगे निस्तारण के लिए भेजे जाने की व्यवस्था के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने मौके पर एफसीटीएस की कार्यप्रणाली को समझा और कचरे के परिवहन तथा निस्तारण व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त कीप्रशिक्षु अधिकारियों का दल इसके बाद भरवारा स्थित सीवेज शोधन संयंत्र पहुंचा। यहां अधिकारियों ने सीवेज के शोधन की पूरी प्रक्रिया को समझा। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार सीवेज को विभिन्न चरणों से गुजारकर शोधित किया जाता है और साफ किए गए पानी का उपयोग निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाता है। अधिकारियों ने सीवेज शोधन संयंत्र में अपनाई जा रही तकनीक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया।स्थलीय अध्ययन के दौरान प्रशिक्षु पीसीएस अधिकारियों ने लखनऊ नगर निगम की कचरा प्रबंधन और सीवेज शोधन व्यवस्था की सराहना की। अधिकारियों ने कहा कि शहर को स्वच्छ और 'शून्य कचरा शहर' बनाने के लिए नगर निगम द्वारा अपनाई जा रही आधुनिक तकनीक और प्रभावी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन, उसके पुनः उपयोग और सीवेज के शोधन से जुड़ी व्यवस्थाओं का लखनऊ मॉडल अन्य शहरों के लिए भी सीखने योग्य है। इस अध्ययन से प्रशिक्षु अधिकारियों को शहरी निकायों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर मिला।

ब्रिक्स शक्ति-संघर्ष का अखाड़ा नहीं, सहयोग का सेतु बने

नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाला 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब विश्व व्यवस्था गहरे संक्रमण से गुजर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का तनाव, आतंकवाद, व्यापारिक टकराव, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा की चिंता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तेज होती चुनौती और वैश्विक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर उठते प्रश्नों ने दुनिया के सामने अनेक अनुत्तरित सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका की व्यापार एवं रणनीतिक नीतियों से पैदा हो रहा दबाव भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। ऐसे वातावरण में भारत की अध्यक्षता में होने वाला यह सम्मेलन केवल एक कूटनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत ने अपनी अध्यक्षता का मूल मंत्र रखा है-लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के आधार पर भविष्य का निर्माण। ब्रिक्स अब 2006 में आरंभ हुई उस मूल अवधारणा से बहुत आगे निकल चुका है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सामने आए थे और बाद में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ। विस्तार के बाद यह 11 सदस्यीय समूह बन चुका है और इसका प्रभाव वैश्विक दक्षिण की राजनीति और अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ा है। वर्ष 2026 ब्रिक्स की स्थापना के दो दशक पूरे होने का वर्ष भी है। भारत के लिए यह अध्यक्षता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह ब्रिक्स को किसी पश्चिम-विरोधी या अमेरिका-विरोधी मंच के रूप में नहीं, बल्कि विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं की रचनात्मक, संतुलित और बहुपक्षीय आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता है।

ब्राजील में 2025 के ब्रिक्स सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने, बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार वैश्विक शासन, जलवायु वित्त, स्वास्थ्य, व्यापार और वित्तीय सहयोग जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण सहमति बनी थी। रियो घोषणा में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया था। साथ ही स्थानीय मुद्राओं में वित्तीय लेन-देन, सीमा-पार भुगतान व्यवस्था और आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने की दिशा में भी आगे बढ़ने की बात कही गई थी। भारत को 2026 की अध्यक्षता सौंपते हुए ब्राजील ने नई दिल्ली से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपेक्षा व्यक्त की थी। इस दृष्टि से दिल्ली सम्मेलन की पहली बड़ी कसौटी यही होगी कि ब्रिक्स घोषणाओं और वास्तविक उपलब्धियों के बीच की दूरी कितनी कम कर पाता है। भारत ने अध्यक्षता के दौरान 25 से अधिक शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग तथा सांस्कृतिक एवं जन-जन संपर्क-इन तीनों क्षेत्रों में व्यावहारिक परिणामों पर जोर दिया गया है। इसलिए अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि सम्मेलन के अंत में केवल लंबा संयुक्त घोषणापत्र सामने आता है या कुछ ऐसे ठोस फैसले भी होते हैं जिनका असर आने वाले वर्षों में दिखाई दे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। एआई ने चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वित्त और शासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं खोली हैं, लेकिन इसके साथ रोजगार, डेटा सुरक्षा, गलत सूचना, साइबर सुरक्षा और तकनीकी असमानता के खतरे भी बढ़े हैं। ब्राजील सम्मेलन में भी एआई के वैश्विक शासन को लेकर व्यापक चिंता व्यक्त की गई थी। भारत अब ब्रिक्स देशों के बीच एआई, उन्नत कंप्यूटिंग, क्वांटम तकनीक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में जोर दे रहा है। यदि ब्रिक्स तकनीक को कुछ शक्तिशाली देशों और कंपनियों के नियंत्रण से बाहर निकालकर विकासशील देशों की पहुंच तक ले जाने की प्रभावी व्यवस्था बना सके, तो यह उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बड़ी चुनौती आर्थिक है। विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स का वजन बढ़ रहा है, लेकिन समूह के भीतर आपसी व्यापार अभी भी उसकी संभावित क्षमता के अनुरूप नहीं है। भारत आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक मजबूत और विविध बनाने, छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने तथा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। जयपुर में हुई ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स इकनोमिक पार्टनरशिप 2030, एमएसएमई के लिए वित्तीय सुविधा और अधिक संतुलित व्यापार जैसे मुद्दों पर प्रगति हुई है। यहां 'डी-डॉलराइजेशन' का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत का दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक है। भारत किसी नई साझा ब्रिक्स मुद्रा के निर्माण की जल्दबाजी में नहीं है। इसके बजाय सीमा-पार डिजिटल भुगतान की ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर जोर है, जिससे सदस्य देश अपनी-अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में अपेक्षाकृत सुगम व्यापार कर सकें।

सत्ता चौबीसों घंटे चलते रंगमंच में बदल गई

नरेंद्र मोदी ने भारत को सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक इवेंट-ग्राउंड बनाया है। और मंच कभी खाली नहीं रहता।

हरिशंकर व्यास

तो अगले एक महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे-मोहरे का अखिल भारतीय प्रोपेगेंडा होगा। हां, सप्ताह में खबर थी कि मोदी ने भाजपा संगठन, नेताओं, मंत्रियों को सात सितंबर से सात अक्टूबर के बीच पच्चीस साला मोदी पावर की इवेंट के कार्यक्रमों का खाका बनवाया है। मतलब मोदी का जन्मदिन (17 सितंबर) उत्सव, सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा, रक्तदान शिविर, मोदी के कामों पर सेमिनार और व्याख्यान आदि-आदि। इसी के लिए दिल्ली में ब्रिक्स बैठक का आयोजन भी है। रूस के पुतिन, चीन के शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री सहित 21 देशों के नेताओं को भारत ने न्योता दिया है। ये आएंगे भी क्योंकि जब दुनिया पुतिन, मसूद पेज़ेशकियान के गले लगने को तैयार नहीं तो दिल्ली में लालकालीन स्वागत, फोटोशूट का मौका कोई क्यों चूके। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान जाएंगे और उसके बाद किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी शामिल होंगे।

ध्यान रहे इन दोनों संगठनों को पश्चिमी देश, अमेरिका चीन का हितधारक मानते हैं। नवंबर में जी-20 की अमेरिका मेजबानी करेगा और डोनाल्ड ट्रंप आए दिन ब्रिक्स के खिलाफ बोलते रहते हैं। पर मोदी के लिए विश्व राजनीति की दिशा-दशा, भारत, उसकी विदेश नीति के दीर्घकालीन हितों का कोई अर्थ नहीं है। उनका मात्र उद्देश्य दुनिया के नेताओं से गले लगने, लगाने और ट्रंप-शी जिनपिंग, पुतिन आदि के साथ फोटो खिंचाने का होता है ताकि भक्त हिंदू उन्हें विश्व नेता की तरह पूजते रहें। और समय-अवसर क्योंकि 25 साला सत्ता का धूमधड़ाका बनाने का है तो विश्व नेताओं के साथ फोटोशूट तो सोने में सुहागा है।

सोचें, मोदी से पहले 1947 से 2014 तक के हर प्रधानमंत्री पर? क्या नेहरू, वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह किसी ने भी जनता को उल्लू बनाने के लिए ऐसा कोई तमाशा किया कि वे इतने-इतने साल सत्ता में रहे तो कांग्रेस या भाजपा और सरकार उनकी महिमा में सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा, सेमिनार और व्याख्यान आयोजित करें! कैबिनेट के मंत्री, मुख्यमंत्री सभी प्रधानमंत्री की आरती उतारें, उनका प्रोपेगेंडा करें!

तो मोदी ऐसा क्यों करते हैं? बकौल लालकृष्ण आडवाणी (अप्रैल 2014)- मैं नरेंद्र भाई को अपना चेला नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने उनसे अधिक प्रतिभाशाली और कुशल इवेंट मैनेजर कभी नहीं देखा। भक्त मूर्ख जन भले न मानें लेकिन नरेंद्र मोदी की सत्ता के 25 साल (13 साल सीएम-12 साल पीएम) में एक-एक साल का, एक-एक महीने की सुर्खियों का हिसाब लगाएं तो 9,130 दिनों में लोगों को बहकाने, भाषण देने, झांकियां दिखाने, नए-नए वादे करने, इवेंट आयोजित करने का मोदी रिकॉर्ड ही निकलेगा।

हां, नरेंद्र मोदी ने भारत को सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक इवेंट-ग्राउंड बनाया है। और मंच कभी खाली नहीं रहता। आज शिलान्यास, कल उद्घाटन; आज संकल्प, कल गारंटी; आज अमृतकाल, कल विकसित भारत। एक पर्दा गिरने से पहले दूसरा उठ जाता है। जनता को हिसाब लगाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, उसके आगे अगली झांकी आ जाती है। उस नाते नरेंद्र मोदी वह राजनीतिक केस स्टडी हैं, जिसमें सत्ता चौबीसों घंटे चलते रंगमंच में बदल गई। हर कुछ सप्ताह में नया सेट, नया नारा, नई झांकी, नया संकल्प और नया भविष्य; केवल नायक स्थायी। दर्शक पिछले दृश्य का हिसाब पूछें, उससे पहले अगला पर्दा उठ चुका होता है।

और इस तथ्य को नोट रखें कि नरेंद्र मोदी का गुजरात का मुख्यमंत्री दफ्तर हो या दिल्ली का प्रधानमंत्री दफ्तर, वह केवल और केवल नौकरशाहों-अफसरों से चलता आया है। नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, या नरसिंह राव, डॉ. मनमोहन सिंह की सत्ता इनके स्वंय के लिखाए नोट, लिखित निर्देशों, विचारों मतलब प्रधानमंत्री के निज दिमाग से चलती थी। नेहरू के 17 वर्षों के कार्यकाल में दफ्तर हो या तीन मूर्ति आवास, दर्जनों स्टेनोग्राफर होते थे। फाइल आती, निर्देश होता तो खुद फाइल पर लिखते या स्टेनोग्राफर से नोट बनवा कर कैबिनेट सचिवों, मंत्रियों, सचिवों को भेजते। और उनके कार्यकाल के आर्काइव की फाइलें इसका प्रमाण हैं।

शास्त्री ने एलके झा को अपने प्रधानमंत्री सचिवालय में रखा लेकिन वे स्वयं अंग्रेजी-हिंदी ड्राफ्ट देखते और सरकार चलाते थे। नरेंद्र मोदी ठीक विपरीत हैं। उनके सीएमओ, पीएमओ के पच्चीस सालों की फाइलें जब आर्काइव में पहुंचेंगी तो उनका राज वैसा ही निकलेगा जैसा बिहार में राबड़ी देवी का था। ध्यान रहे देश के दूसरे बड़े प्रांत बिहार में राबड़ी देवी का साढ़े सात साल शासन रहा। वे भी अफसरों के बनाए नोट, फाइलों, कैबिनेट बैठकों के एजेंडा (राज्यों में मुख्य सचिव और दिल्ली में कैबिनेट सचिव) की उस सत्ता से चलती थीं, जैसे नरेंद्र मोदी चलते हैं। राबड़ी देवी को सलाह देने वाली अधिकारी राजबाला वर्मा हुआ करतीं। वे नोट बनाती थीं, फाइल प्रोसेस करती थीं, मुख्यमंत्री के दस्तखत की जगह लाइन खींच देती थीं और उस जगह राबड़ी देवी जैसे-तैसे दस्तखत करती थीं।

ऐसे ही नरेंद्र मोदी के गांधीनगर सीएमओ में 2001 में उनके प्रमुख सचिव डॉ. पीके मिश्रा थे तो वे आज भी प्रधानमंत्री दफ्तर में उनके प्रमुख सचिव हैं। जैसे लालू-राबड़ी या नीतीश कुमार के 1990 से 2025 तक 35 वर्षों के चंद अफसरों से बिहार की दशा-दिशा, नियति बनी, वही मोदी के 25 साला गुजरात-भारत की दशा-दिशा और सेहत का समय है। यह रियलिटी भारत की मंडल, कमंडल राजनीति में हिंदुओं की उस दशा को जाहिर करती है, जिसका डीएनए है 'कोऊ नृप होउ हमहि का हानीÓ या जो सत्तावान है वही हुकूम है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं!

इसमें नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत की राजनीति में मील के पत्थर हैं। क्योंकि उन्होंने अफसरों को शासन का कोर बना कर सरकार याकि प्रधानमंत्री के पद को ऐसा रंगमंच बनाया है, जिसमें अभिनेता एक ही है और वह हर महीने, हर दिन नया सेट, नया संवाद, नया उद्घाटन, नई झांकी से भक्तों को रिझाता रहता है। उनके शासन का भाषण, घोषणा अगली घोषणा तक जीवित रहती है, फिर नया पर्दा उठता है और पिछला दृश्य, दिखाया सपना यादगार से आउट हो जाता है। उनकी राजनीति मदारी, जादूगर जैसी नहीं, बल्कि एक आधुनिक स्टूडियो जैसी है। कब गले लगेंगे, रोशनी कहां पड़ेगी, कैमरा कहां रहेगा और दर्शक किस ओर देखेगा, इसकी पहले तैयारी होती है। वे स्वयं मंच-निर्देशक हैं, अभिनेता हैं और सरकार उनकी पटकथा। नौकरशाही प्रोडक्शन टीम और हर बड़ी तारीख एक नया प्रीमियर। सो, अगला सितंबर का शो ब्रिक्स है और सात सितंबर से सात अक्टूबर के बीच देश भर में मोदी की पच्चीस साला सत्ता का भगवा कीर्तन!

व्यंग्य

मीडिया कवरेज का अनुरोध

मोदी पत्रकारों के सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करते, यह जग-जाहिर है। इसलिए भारत का प्रेस कांफ्रेंस ना रखने का अनुरोध असामान्य नहीं है। असामान्य अमेरिका का उस अनुरोध के प्रति दिखाई गई बेकद्री है।

कूटनीतिक स्तर पर हुए संदेशों के आदान-प्रदान की सार्वजनिक चर्चा कर अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जताया है कि ट्रंप काल में अमेरिका के मन में भारतीय नेतृत्व के प्रति कितनी बेकद्री भरी हुई है। जो उन्होंने बताया, उनसे यह और भी स्पष्ट हुआ। यह सवाल भारत सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर यह स्थिति उसने क्यों बनने दी है? भारत में अमेरिकी राजदूत गोर ने एक कार्यक्रम में बताया कि जून में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने का कार्यक्रम बना, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने अनुरोध किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें लेने की अनुमति दी जाए, लेकिन सवाल-जवाब वाली पूरी कॉन्फ्रेंस ना रखी जाए।

गोर ने यह नहीं कहा, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की इस शर्त पर अमेरिका सहमत हुआ। लेकिन मुलाकात के बाद मोदी और डॉनल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए, तो शुरुआती बयान पूरा होते ही ट्रंप ने वहां मौजूद पत्रकारों से खुद ही पूछ लिया कि क्या 'कोई सवाल है?' उसके बाद वे 45 मिनट तक सवालों के जवाब देते रहे, जबकि मोदी खामोश बैठे रहे। इस खुलासे से बनी असहज स्थिति के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि किसी शीर्ष नेता के विदेशी दौरों से पहले मीडिया में उनकी उपस्थिति के प्रारूप को लेकर संबंधित देशों के बीच चर्चा होना 'मानक प्रोटोकॉल' है। भारतीय पक्ष ने अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ही मीडिया कवरेज का अनुरोध किया।

मोदी पत्रकारों के सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करते, यह जग-जाहिर है। इसलिए भारत की तरफ से ऐसा अनुरोध असामान्य नहीं है। असामान्य अमेरिका का उस अनुरोध के प्रति दिखाई गई बेकद्री है। अपेक्षित था कि ट्रंप के उस व्यवहार पर भारत सरकार तुरंत सार्वजनिक विरोध जताती। मगर ऐसा नहीं किया गया। अब घरेलू जनमत को संभालने के लिए 'सरकारी सूत्रों' से ब्रीफिंग कराई गई है कि मीडिया के सामने विदेशी नेताओं के साथ ट्रंप के 'अप्रत्याशित व्यवहार' के कारण उपरोक्त अनुरोध किया गया। इस बात में सच्चाई हो सकती है, लेकिन असल मुद्दा उस अनुरोध के प्रति का ट्रंप का रहा व्यवहार है।

ब्लॉग

हमारी आंगनवाड़ी, हमारी ज़िम्मेदारी

जब समुदाय अपनी आंगनवाड़ी को अपना मानता है

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

2047 का विकसित भारत उन बच्चों के हाथों से बनेगा, जो अभी स्कूल की दहलीज तक भी नहीं पहुँचे हैं। स्वस्थ और सक्षम बनने की उनकी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण नींव जीवन के पहले एक हजार दिनों में ही रखी जाती है। करोड़ों भारतीय बच्चों और माताओं के लिए इस सफर का भरोसेमंद सहारा उनके आसपास ही मौजूद है—आँगनवाड़ी।

स्कूल जाने से बहुत पहले बच्चे का वजन और लंबाई आँगनवाड़ी में मापी जाती है। वहीं उसे गरम पका भोजन और घर के बाहर की दुनिया से जुड़ने का पहला अवसर मिलता है, और गर्भवती माँ को पोषण से जुड़ी पहली सलाह भी। देशभर के लगभग 14 लाख आँगनवाड़ी केंद्र 8.9 करोड़ से अधिक बच्चों, महिलाओं और किशोरियों तक पहुँच रहे हैं, और इन्हें चलाने वाली 25.2 लाख कार्यकर्ता व सहायिकाएँ उसी समाज से आती हैं, जिसकी वे सेवा करती हैं। आँगनवाड़ी हमारे समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं, हमारे अपने पड़ोस का हिस्सा है।

मार्च 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पोषण अभियान की शुरुआत कर इसी परिचित व्यवस्था को देशव्यापी जनआंदोलन की मजबूत नींव बनाया। तब से हर सितंबर राष्ट्रीय पोषण माह और हर मार्च पोषण पखवाड़ा पोषण का संदेश देश के कोने-कोने तक पहुँचाने का माध्यम बने हैं।

इस वर्ष 9वाँ राष्ट्रीय पोषण माह 9 सितंबर 2026 से हमारी आँगनवाड़ी, हमारी ज़िम्मेदारी थीम के साथ शुरू हो रहा है। गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में हमारा संकल्प मजबूत है। साथ ही, इन सेवाओं का प्रभाव तब और बढ़ता है, जब समुदाय आँगनवाड़ी को अपना मानता है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से होगा।

लाभार्थी से भागीदार तक

इस वर्ष सामुदायिक भागीदारी को एक व्यवस्थित रूप दिया जा रहा है। आँगनवाड़ी प्रबंधन समितियाँ माता-पिता, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूहों को केंद्र के संचालन से जोड़ती हैं। वे देख सकते हैं कि बच्चों को क्या परोसा जा रहा है, हर हकदार बच्चे तक सेवाएँ पहुँच रही हैं या नहीं, और केंद्र को बेहतर बनाने के लिए किस सहयोग की आवश्यकता है। इसे प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है—सोशल ऑडिट, जो समुदाय को अपनी आँगनवाड़ी की समीक्षा करने और सामने आने वाली बातों के आधार पर सुधार की दिशा तय करने का अवसर देता है। जिस केंद्र से बच्चों और माताओं का जीवन जुड़ा है, उसकी गुणवत्ता बनाए रखने में उन्हीं परिवारों की भागीदारी सबसे स्वाभाविक है।

इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में माँ है, और उसके हाथ में पारदर्शिता का सरल माध्यम है—मेन्यू बोर्ड। हर केंद्र पर लगा यह बोर्ड गरम पके भोजन और टेक-होम राशन का दिन-वार विवरण परिवारों के सामने रखता है। जब एक माँ जानती है कि उसके बच्चे को क्या मिलना चाहिए और केंद्र के साथ संवाद कर यह सुनिश्चित करती है कि उसे तय मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार भोजन मिले, तो पारदर्शिता रोजमर्रा की व्यवस्था बन जाती है।

पोषण माह 2026 इसी भागीदारी को जमीन पर उतारने का अवसर है। जहाँ प्रबंधन समितियाँ गठित नहीं हुई हैं, वहाँ उनका गठन किया जाएगा; जहाँ मौजूद हैं, वहाँ उनकी पहली बैठकें और सोशल ऑडिट होंगे। हर केंद्र पर मेन्यू बोर्ड लगेगा। तिथि भोज और स्वस्थ व्यंजनों के प्रदर्शन जैसे आयोजन परिवारों, पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों को आँगनवाड़ी के और करीब लाएँगे।

मेन्यू बोर्ड से आगे

आँगनवाड़ी सेवाओं की पहली कसौटी है—पौष्टिक भोजन, जो संतुलित और विविधतापूर्ण भी हो: अनाज और श्री अन्न, दालें, मेवे और बीज, दूध और दुग्ध उत्पाद, अंडा, मौसमी फल तथा हरी सब्जियाँ। इसी दिशा में जुलाई में जारी पूरक पोषण कार्यक्रम के व्यापक दिशानिर्देश, 2026 महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनमें पहली बार गरम पके भोजन का स्वरूप स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के पोषक मानकों को और मजबूत किया गया है।

भोजन के साथ बच्चे के शुरुआती विकास और सीखने पर भी उतना ही ध्यान जरूरी है। बच्चा क्या खाता है और कैसे सीखता है—दोनों गहराई से जुड़े हैं। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता पहले तीन वर्षों में विकास के 34 पड़ावों पर नजर रखती हैं, और नवचेतना तथा आधारशिला जैसे पाठ्यक्रम बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करते हैं।

यह यात्रा जन्म से भी पहले शुरू होती है—गर्भावस्था में माँ का पोषण बच्चे के जीवन की शुरुआत को भी प्रभावित करता है। इसी संदर्भ में इस वर्ष प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के दस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके पीछे भावना यही रही है कि किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान अपनी आजीविका और अपने स्वास्थ्य के बीच चुनाव न करना पड़े। इन दस वर्षों में 4.65 करोड़ लाभार्थियों तक ?21,511 करोड़ सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचे हैं। मिशन शक्ति के तहत यह योजना अब दूसरी संतान के रूप में बेटी के जन्म पर अतिरिक्त लाभ भी देती है।

सहायता का प्रभाव तब कई गुना बढ़ जाता है, जब वह अकेले नहीं, बल्कि निरंतर परामर्श और सहयोग के साथ पहुँचती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भी इसी तथ्य को रेखांकित किया है कि नकद सहायता अपना पूर्ण उद्देश्य तभी सिद्ध करती है, जब उसके साथ ऐसा परामर्श भी जुड़ा हो, जो परिवार को सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाए। सर्वेक्षण में राजस्थान के कैश प्लस मॉडल का उल्लेख है, जिसमें नकद सहायता के साथ सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संवाद को योजना का अभिन्न अंग बनाया गया। परिणाम यह हुआ कि सहायता राशि को भोजन पर व्यय करने वाली महिलाओं का अनुपात 30 प्रतिशत से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया, और जैसे-जैसे पति तथा परिवार के अन्य सदस्य इस संवाद से जुड़ते गए, मातृ पोषण से जुड़ी भ्रांतियाँ भी दूर होती गईं। शिशु का पोषण केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं—इसमें परिवार, समुदाय और व्यवस्था, सभी की भूमिका है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सम्मान

इस पूरे प्रयास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता है। सामुदायिक भागीदारी का उद्देश्य उसका दायित्व बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे सहयोग और सम्मान देना है। स्थानीय परिवारों की जो समझ और भरोसा उन्होंने वर्षों में बनाया है, वह इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। जब कार्यकर्ता के साथ समुदाय खड़ा होता है, तो आँगनवाड़ी की ताकत कई गुना बढ़ जाती है।

इस सितंबर, मैं हर नागरिक से अपील करती हूँ कि वह अपने क्षेत्र की कम से कम एक आँगनवाड़ी अवश्य जाए। कार्यकर्ता से बात कीजिए, मेन्यू बोर्ड पढ़िए, बच्चों को मिल रही सेवाओं के बारे में जानिए—और सबसे महत्वपूर्ण, पूछिए कि आप क्या सहयोग कर सकते हैं।

इस सितंबर जिन बच्चों का वजन आँगनवाड़ी केंद्रों में लिया जा रहा है, वे 2047 में लगभग बीस-पच्चीस वर्ष के होंगे। वे जिस स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और क्षमता के साथ देश के विकास में योगदान देंगे, उसकी नींव आज रखी जा रही है। जब हर समुदाय अपनी आँगनवाड़ी को अपनी ज़िम्मेदारी मानकर उसके साथ खड़ा होता है, तब हर बच्चे का भविष्य और मजबूत होता है।

लेखिका भारत सरकार में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं

नितिन हत्याकांड: धरने पर बैठे मंत्री, शव रखकर मेरठ-बिजनौर मार्ग किया जाम, मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। हस्तिनापुर के माखननगर निवासी नितिन की गोली मारकर हत्या के बाद शनिवार को ग्रामीणों और परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही गणेशपुर तिराहे पर मेरठ-बिजनौर मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया गया। दोनों ओर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया गया। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुटे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी तथा एनकाउंटर की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसी बीच हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपी मिट्ठू पुत्र पिंकी चौधरी के घर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई की।

शनिवार सुबह गणेशपुर तिराहे पर ग्रामीणों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद नितिन

का शव पहुंचते ही ग्रामीणों और परिजनों का आक्रोश बढ़ गया। शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया और दोनों ओर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर मेरठ-बिजनौर मार्ग बंद कर दिया गया। इससे मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर भेजी गई।

आरोपियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की मांग थी कि नितिन की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। ग्रामीणों ने आरोपियों के एनकाउंटर की भी मांग उठाई। परिजनों और ग्रामीणों का कहना था कि जब तक पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं देते और सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, तब तक शव नहीं उठाया जाएगा।

पुलिस पर लापरवाही का आरोप

ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि यदि पुलिस पहले सक्रिय होती तो हत्या की घटना रोकी जा सकती थी। ग्रामीणों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।

पुलिस अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया

जाम और हंगामे की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन ग्रामीण कार्रवाई के स्पष्ट आश्वासन पर अड़े रहे। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

मुख्य आरोपी मिट्ठू के घर चला बुलडोजर

ग्रामीणों के प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने हत्याकांड के फरार मुख्य आरोपी मिट्ठू पुत्र पिंकी चौधरी के घर पर बुलडोजर चलवाया। कार्रवाई के दौरान एसपी देहात अभिजीत कुमार और सीओ पंकज लवानिया मौके पर मौजूद रहे। पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार, नितिन की शुक्रवार शाम हत्या के बाद से ही आरोपी फरार हैं। मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के तहत शनिवार को उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया।

चार पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में

नितिन हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमें गठित की गई हैं। टीमें अलग-अलग स्थानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ घटना में इस्तेमाल हथियारों और हत्या के कारणों की भी जांच कर रही है।

प्रिंस पर हमले के दौरान नितिन को लगी थी गोली

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पास प्रिंस उर्फ मुकद्दम पर जानलेवा हमला हुआ था। उस दौरान उसके पीछे बाइक पर बैठे नितिन को गोली लग गई। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।

तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई

परिजनों की ओर से तहरीर दिए जाने की प्रक्रिया के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर दबाव बढ़ गया है।

चार पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, आन्दोलन खत्म

जौनपुर। एक लेखपाल से दुयवहार के मामले में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद लेखपाल संघ ने अपना काम बंद आंदोलन खत्म कर दिया।यह कार्रवाई सदर तहसील में कार्यरत लेखपाल हिमांशु यादव के साथ हुए दुयवहार के बाद की गई। एसओजी टीम किसी और को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान गलतफहमी में उन्होंने लेखपाल हिमांशु यादव को पकड़ लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अधिकारियों से बातचीत के बाद पुलिस अधीक्षक ने क्राइम ब्रांच के चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया।इनमें हेड कांस्टेबल प्रफुल्ल यादव, हेड कांस्टेबल आशुतोष सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव और कांस्टेबल विनीत यादव शामिल हैं। इस घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के सदर अध्यक्ष विक्रांत सिंह चैहान के नेतृत्व में लेखपालों ने प्रदर्शन किया था।

संक्षेप

विशाल यादव हत्याकांड में दो गिरफ्तार

जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामदयालगंज में दिनदहाड़े युवक विशाल यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार नीरज यादव निवासी गहोरा और मनीष यादव निवासी चांदपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक पूर्व रंजिश को लेकर हुई मारपीट के दौरान लोहे की रॉड से हमला किए जाने से विशाल यादव की मौत हो गई थी। घटना के बाद लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी नीरज यादव के खिलाफ वर्ष 2021 से 2026 तक कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें आयुध अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट, धमकी, एससीध्एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं के मामले शामिल हैं। वहीं मनीष यादव के खिलाफ भी वर्ष 2016 से अब तक कई आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं के मुकदमे शामिल हैं।

संत निरंकारी मिशन का रक्तदान शिविर आज

जौनपुर। आध्यात्मिकता ही मानव एकता को मजबूती दे सकती है तथा मानव को मानव के निकट लाकर आपसी प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना सकी है। इसी मन्तव्य से 13 सितंबर रविवार को संत निरंकारी सत्संग भवन ब्रांच - थाना गद्दी, में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जिसका समय प्रातः 10 से 2 बजे तक है। इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए जनपद के 43 ब्रांचो से श्रद्धालु भक्त पूरे जोश एवं उत्साह से रक्तदान करेंगे। इस रक्तदान शिविर में रक्त संग्रहित करने हेतु जिला अस्पताल (सदर) के प्रशिक्षित डाक्टर एवं टीम सम्मिलित होंगी। जोनल इंचार्ज ी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि युगप्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी समाज कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। प्रत्येक भक्त के जीवन को वास्तविक रूप में एक व्यावहारिक दिशा प्रदान की जिसके लिए मानवता उनकी सदैव ही ऋणी रहेगी। निश्चित रूप में लोक कल्याण हेतु चलाया जा रहा यह अभियान निरंकारी सतगुरु की प्रदत्त सिखलाइयो को दर्शाते हुए एक दिव्य संदेश प्रेषित कर रहा है जिससे हर प्राणी प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा है।

सपा को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर

जौनपुर। समाजवादी पार्टी जौनपुर की मासिक बैठक शनिवार को समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय, सदर चुंगी अल्फस्टीनगंज, में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्री श्यामबहादुर पाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्यामबहादुर पाल ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने तथा पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया।बैठक को प्रदेश सचिव सुशील दुबे, जिला उपाध्यक्षगण हीरालाल विश्वकर्मा, सुरेश यादव, उमाशंकर पाल, जिला सचिवगण राजदेव पाल, कैलाशनाथ यादव ,भूपेश पाण्डेय, कमलेश यादव, रामकेश बिंद, दीपक विश्वकर्मा तथा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षगण रामजतन यादव, वीरेंद्र यादव, नंदलाल यादव, रामू मौर्य एडवोकेट, अजय विश्वकर्मा, जगदीश प्रसाद मौर्य 'गप्पू', रवि यादव, रामलले यादव, डॉ. अमित यादव, चंद्रशेखर यादव, शर्मिला रमेश, डॉ. निकहत हसन, हरिश्चंद प्रभाकर, अच्छेलाल गौतम, विजय बहादुर गौतम, अशोक यादव नायक, दिलीप प्रजापति, रामभिलाष यादव, जितेंद्र यादव आदि ने संबोधित किया।

अवधेश सिंह अध्यक्ष और मनीष सिंह मंत्री निर्वाचित

जौनपुर। दीवानी अधिवक्ता संघ के चुनाव में अवधेश सिंह ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की, जबकि मनीष सिंह को मंत्री पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में उत्साह का माहौल रहा। अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को मजबूत बनाने और अधिवक्ताओं के हितों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने की उम्मीद जताई। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विजयी प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

मूल्यों की राजनीति के प्रबल पक्षधर थे उमानाथ सिंह

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्व. ठा. उमानाथ सिंह की पुण्यतिथि पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया जा रहा है। उनके निधन को 32 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन त्याग, परोपकार, सादगी, विनम्रता, धैर्य और समर्पण से जुड़ी उनकी स्मृतियां आज भी लोगों के बीच जीवंत हैं। वह मूल्यों की राजनीति में विश्वास करते थे और जिले के विकास के लिए आजीवन संघर्षशील रहे।राजनीतिक जीवन में स्व. उमानाथ सिंह की अलग पहचान थी। गरीबों और असहायों के हितों के लिए वह सदैव तत्पर रहते थे। अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने वाले हर व्यक्ति की बात वह सहजता से सुनते और उसके समाधान का प्रयास करते थे। मृदुभाषी स्वभाव के कारण सभी राजनीतिक दलों में उनका सम्मान था। उनके विचारों से विभिन्न दलों के कई वरिष्ठ नेता प्रभावित रहते थे।मोहल्ला नखास स्थित उनके आवास की चैखट आम लोगों के लिए हमेशा खुली रहती थी। बरामदे में चैकी पर बैठकर वह समर्थकों और फरियादियों से सहजता से मिलते थे। गरीब और जरूरतमंद लोग बिना किसी संकोच के अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते थे। उनका मानना था कि सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंततः परिणाम सत्य के पक्ष में ही जाता है।स्व. उमानाथ सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर साहित्य वाचस्पति श्रीपाल सिंह क्षेम की लिखी कविता भी उनके सामाजिक और मानवीय व्यक्तित्व को रेखांकित करती है। उनके परिवार में उन्होंने जो संस्कार बोए, वे आज भी उनकी विरासत के रूप में दिखाई देते हैं। उनके अनुज एवं टीडी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्व. अशोक सिंह ने भी अपने बड़े भाई की स्मृति में शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर समाजसेवा की मिसाल कायम की। कोरोना काल में स्व. अशोक सिंह का निधन हो गया, लेकिन जीवनभर उन्होंने अपने बड़े भाई के पदचिह्नों पर चलने का प्रयास किया।स्व. उमानाथ सिंह के संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए उनके पुत्र पूर्व सांसद कृष्ण प्रताप सिंह 'केपी' तथा परिवार के अन्य सदस्य राघवेंद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, शिवेंद्र प्रताप सिंह और शिवेंद्र प्रताप सिंह समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। सिंह के भतीजे राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को तिलकधारी महाविद्यालय के बलरामपुर हाल में दोपहर 12 बजे से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय शुल्क राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव मौजूद रहेंगे।

अली ने नहीं दिए नए मुलाकाती के नाम, मिलने भी न आया कोई अपना ; छोटा भाई ही संभालता था ये जिम्मेदारी

आर्यावर्त संवाददाता

झांसी। करीब 11 महीने से झांसी जेल में बंद अली अहमद से छोटे भाई अबान की मौत के बाद मिलने के लिए कोई अपना नहीं पहुंचा है। हादसे में अबान की मौत को एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस दौरान अली का कोई परिजन जेल में उससे मिलने नहीं आया। अली ने भी जेल प्रशासन को किसी नए रिश्तेदार का नाम मुलाकाती के तौर पर दर्ज कराने के लिए नहीं दिया है। फिलहाल उससे मिलने के लिए सिर्फ उसके वकील ही जेल पहुंच रहे हैं।

दिवंगत माफिया अतीक अहमद का बेटा अली एक अक्तूबर 2025 से झांसी जेल में बंद है। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की 6 अगस्त 2026 को झांसी-कानपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अबान अली से नियमित मुलाकात के लिए झांसी आ रहा था। झांसी-कानपुर हाईवे पर पूछ के खिल्ली गांव के पास अबान की तेज रफ्तार कार रिटेनिंग वाल से जा टकराई थी, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

बड़े भाई अली से मिलने के लिए उसका छोटा भाई अबान नियमित रूप से प्रयागराज से झांसी आता था। अबान 30 से अधिक बार जेल में अली से मुलाकात कर चुका था। अली अपनी पसंद की चीजें भी अक्सर अबान से ही मंगवाता था। छह अगस्त को भी अबान अली से मिलने के लिए झांसी आ रहा था। झांसी-कानपुर हाईवे पर पूंछ के खिल्ली गांव के पास उसकी तेज रफ्तार कार सड़क किनारे बनी सहारा दीवार से टकरा गई थी। हादसे में अबान की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद से अली से मिलने के लिए परिवार का कोई सदस्य झांसी जेल नहीं पहुंचा है। अली को भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रयागराज ले जाया गया था।

इस दौरान उसने अपने मंझले भाई अहजम को भी झांसी जेल में आकर उससे मुलाकात करने से मना

कर दिया था। इसके बाद भी उसने किसी अन्य रिश्तेदार का नाम मुलाकाती के तौर पर जेल प्रशासन को नहीं दिया।

वकील ही बने मुलाकात का सहारा

अबान की मौत के बाद बीते एक माह से अली से मिलने के लिए उसके वकील ही जेल पहुंच रहे हैं। परिवार का कोई सदस्य मुलाकात के लिए नहीं आया है। अली ने भी अब तक किसी रिश्तेदार को मुलाकाती के तौर पर दर्ज नहीं कराया है।

वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि अली ने अब तक किसी रिश्तेदार का नाम मुलाकाती के तौर पर दर्ज कराने के लिए जेल प्रशासन को नहीं दिया है। उससे मिलने आने वालों का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। सुरक्षा के मद्देनजर मुलाकातियों की सूचना एलआईयू को भी दी जाती है।

अबान संभालता था अली से मुलाकात की जिम्मेदारी

अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। उमर से मिलने के लिए उनका मंझला भाई अहजम जाता था, जबकि अली से मिलने की जिम्मेदारी अबान संभालता था। अबान तकरीबन हर सप्ताह अली से मिलने झांसी आता था। उसकी मौत के बाद से यह सिलसिला पूरी तरह थम गया है।

130 किमी रफ्तार, दस फीट उछली, फिर दाएं पहिये पर गिरी कार

झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में खुलासा हुआ है। अबान की कार हादसे से पहले करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। इसका खुलासा हादसे के बाद तकनीकी जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है। तकनीकी जांच कमेटी ने हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार का मुआयना किया, उसके बाद यह रिपोर्ट सौंपी गई थी। रिपोर्ट से हादसे की तो पुष्टि होती है लेकिन, इसके पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी हालांकि दुर्घटना के हालत को देखते हुए चालक को झपकी आने की संभावना जताई जा रही है। जांच रिपोर्ट लखनऊ आला पुलिस अफसरों को भी भेजी गई है। छह अगस्त की सुबह प्रयागराज से झांसी आते समय झांसी-कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास अबान की कार हाईवे की सुरक्षा दीवार से जा भिड़ी थी।

हादसे के बाद तकनीकी जांच के लिए परिवहन विभाग के आरआई राघव कुमार एवं एमटी (तकनीकी) प्रभारी शिव कुमार की अगुवाई में टीम बनाई गई। जांच के दौरान टीम ने कार के ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, पहिये, व्हील अलाइनमेंट, वाहन की बॉडी का क्रश पैटर्न, पैसेंजर कंपार्टमेंट, एयरबैग और सीट-बेल्ट सिस्टम की जांच की। जांच में यह भी देखा गया कि हादसे से पहले कार में कोई यांत्रिक खराबी तो नहीं थी।

अबान की कार में बायां फ्रंट हिस्सा कंक्रीट की कठोर दीवार से टकराने के बाद पीछे की सीट तक धंस गया था। हादसे के बाद कार का हाल देखकर यह पता चला कि उस समय उसकी रफ्तार 130 किलोमीटर के करीब थी। इसी रफ्तार में कार सीधे कंक्रीट की मजबूत सुरक्षा दीवार से जा टकराई थी।

जनगणना के प्रक्षिण में लिया कर्मियों ने भाग

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण जनसंख्या की गणना के सम्बंध में डायट जौनपुर में अहम प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण में जिले के सभी तहसीलों एवं नगर निकायों के सहायक चार्ज अधिकारी, जनगणना लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण सत्र में जनगणना निदेशालय के प्रतिनिधि युवराज गर्ग ने गणना ब्लॉक के गठन, पुराने गणना ब्लॉक की पॉपुलेशन रेशनलाइजेशन करना, जनगणना कार्य में लगने वाले कार्मिकों का डेटाबेस तैयार करने हेतु आवश्यक इंस्ट्रक्शन्स दिये गये। जनगणना द्वितीय चरण में कुल 40 प्रश्न होंगे एवं जो जहां है वहीं उसकी गणना होगी स्व-गणना की तिथि 16 नवंबर से 30 नवंबर तक होगी एवं जनसंख्या की गणना का कार्य 01 दिसम्बर से 04 जनवरी 2027 तक होगा। जनगणना निदेशालय के प्रतिनिधि युवराज गर्ग ने सभी चार्ज अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों से जनगणना के द्वितीय चरण के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कार्यों में शुद्धता एवं समयबद्धता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। प्रशिक्षण के दौरान जिला जनगणना लिपिक हर्षित श्रीवास्तव एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर उमेश चन्द्र मिश्र, कमलेश यादव एवं अजय मौर्य ने संबंधित कर्मचारियों को जनगणना कार्यों की बारीकियों, तकनीकी प्रक्रिया और आवश्यक सावधानियों से अवगत कराया।

लापता अधेड़ का धान के खेत में मिला शव

जौनपुर। रामपुर थाना क्षेत्र के सपही गांव निवासी 56 वर्षीय लल्लन गौतम का शव शनिवार सुबह साधीरनगंज बाजार के पास धान के खेत में पानी के बीच मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लल्लन 10 सितंबर को साइकिल से साधीरनगंज बाजार गए थे, लेकिन इसके बाद घर वापस नहीं लौटे। बाजार के पास धान के खेत में पानी के बीच शव दिखाई देने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच-पड़ताल की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, लल्लन गौतम की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

बाबा नीब करौरी जन्मस्थली विवाद: घरौनी संशोधन पर रोक से फंसेगा पेच, छह पोतियों और ट्रस्टी को नोटिस, मांगे सबूत

आर्यावर्त संवाददाता

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के टूंडला के अकबरपुर स्थित प्रख्यात संत बाबा नीब करौरी की जन्मस्थली के पैतृक मकान पर उठे स्वामित्व विवाद में जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। डीएम के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय जांच समिति के अध्यक्ष एवं एडीएम (न्यायिक) अरविंद द्विवेदी ने बाबा की छह पोतियों तथा श्री ठाकुर हनुमानजी ट्रस्ट के पदेन ट्रस्टी संजय गुप्ता को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन ने दोनों पक्षों से अपनी-अपनी दावेदारी, साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। ताकि प्रकरण की निष्पक्ष सुनवाई कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा सके।

बाबा नीब करौरी (लक्ष्मी नारायण शर्मा) के छोटे पुत्र स्वर्गीय धर्म नारायण शर्मा की छह पुत्रियों

सुनीता, अर्चना, वंदना, भावना, रितु और रिचा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को अगस्त माह में प्रार्थना पत्र सौंपा था।

ग्राम पंचायत नगला स्थित मकान संख्या 154-व (बाबा का ध्यान कक्ष, भोजनालय व शयन कक्ष) पर श्री ठाकुर हनुमानजी ट्रस्ट के ट्रस्टी संजय गुप्ता ने एकाधिकार कर लिया है। मुंबई से आए भावना रावत के पति मनोज रावत ने डीएम से मुलाकात कर पैतृक संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने और विवाद के स्थायी समाधान के लिए डीएम की अध्यक्षता में शासकीय प्रशासनिक ट्रस्ट बनाने की मांग रखी थी।

वर्तमान में शासन द्वारा अकबरपुर में बाबा नीब करौरी धाम कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। एडीएम अरविंद द्विवेदी ने बताया कि प्रशासन ने नोटिस जारी कर सभी पक्षों को साक्ष्य देने के लिए कहा है।

1996 में बाबा की पत्नी रामबेटी ने कराया था ट्रस्ट का गठन

श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ट्रस्ट का गठन वर्ष 1996 में बाबा की धर्मपत्नी स्वः रामबेटी शर्मा द्वारा किया गया था। कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में ट्रस्ट में 18 सदस्य हैं और बाबा की आगरा निवासी बेटी गिरजा भटेले स्वयं इसकी अध्यक्ष हैं।

इसके अलावा बाबा के बड़े बेटे स्वः अनेक सिंह शर्मा की बड़ी बेटी सुनीता शर्मा के पति त्रिलोकी चंद्र शर्मा, दूसरी बेटी अर्चना शर्मा और बेटे डॉ. धनंजय शर्मा भी ट्रस्ट में शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी सदस्य सेवा भावना से कार्य कर रहे हैं और संपत्ति का कोई निजी उपयोग नहीं हो रहा है, जो भी निष्पक्ष होकर सेवा करना चाहता है, उसका स्वागत है।

ट्रस्ट पर एकाधिकार ठीक नहीं: मनोज रावत

शिकायतकर्ता पोतियों में शामिल भावना रावत के मुंबई निवासी पति मनोज रावत का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि इस ट्रस्ट पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने प्रशासन के समक्ष डीएम की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि बाबा की संपत्ति का कोई दुरुपयोग न हो।

घरौनी संशोधन पर रोक से फंसेगा विधिक पेच

प्रशासन ने एक ओर जांच शुरू कर दी है। मगर, मामले में एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी पेच यह फंस गया है कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा घरौनी में संशोधन की मांग भी की गई है। जबकि, वर्तमान में प्रदेश स्तर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (राजस्व परिषद) द्वारा घरौनियों में किसी भी प्रकार के संशोधन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में राजस्व नियमों की बंदिशों के बीच जिला प्रशासन इस विवाद का क्या विधिक समाधान निकालता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

बाबा नीब करौरी की जन्मस्थली पहुंचे डीएम, पर्यटन विकास कार्यों का लिया जायजा

जिले में स्थित बाबा नीब करौरी महाराज की जन्मस्थली टूंडला के ग्राम अकबरपुर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर सजाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने विकास कार्यों और प्रस्तावित भव्य कॉरिडोर की समीक्षा की।

डीएम ने बताया कि उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन नीति-2022 में संशोधन कर नीब करौरी बाबा सर्किट को शामिल किया था। जिसके तहत लखनऊ, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और मथुरा/वृंदावन को आपस में जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार व निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे।

फेज-1 में लागत 865.98 लाख से डॉरमेट्री, रेस्तरां, सभा स्थल, डिजिटल लाइब्रेरी, सीसी रोड, सेप्टिक टैंक, समरसेबुल पंप तथा साइट डेवलपमेंट के कार्य प्रगति पर हैं। फेज-2 में लागत 222.47 लाख से टॉयलेट ब्लॉक, गार्ड रूम, सीसी रोड, नाली, पेवर, ट्यूबवेल, बाह्य विद्युत कार्य एवं म्यूरल वर्क स्वीकृत किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण के बाद यहां भव्य प्रवेश द्वार, पर्यटन सुविधा केंद्र, ध्यान व वेलनेस सेंटर, फूड कोर्ट, म्यूजियम, ओपन एयर थिएटर, पार्किंग और प्रसाद मंडप जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं तैयार की जाएंगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम टूंडला मौजूद रहे।

एनुअल चेकअप करवाने से किसी भी डिजीज का किया जा सकता है अर्ली डिजीज डिटेक्शन, क्यों है यह जरूरी

केवल डॉक्टरों के लिए ही नहीं बल्कि मरीजों के लिए भी तकनीक लाभदायक है। बहुत से मोबाइल हेल्थ ऐप और वेबसाइट मरीजों के लिए उपलब्ध है जहां वह अपने चेक अप या हेल्थ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।

अर्ली डिसीस डिटेक्शन का अर्थ होता है किसी बीमारी को समय से ही पकड़ लेना या उसके बारे में ज्यादा गंभीरता से पहले पता लगा लेना। ऐसे में लक्षण दिखने से पहले ही किसी भी बीमारी को पकड़ लिया जाता है और उसका इलाज समय से ही शुरू कर दिया जाता है ताकि वह बीमारी अपनी और गंभीर स्टेज में प्रवेश न कर सके।

इस प्रक्रिया के लिए काफी सारी तकनीकों और टूल्स का प्रयोग किया जाता है। आपको हमेशा अपने एनुअल चेक अप करवाते रहना चाहिए और उस दौरान अगर कोई भी बीमारी शुरुआती स्टेज में भी होगी तो उसका डायग्नोसिस संभव हो सकता है ताकि प्रभावी रूप से आपका इलाज हो सके।

यह तकनीक उन बीमारियों के केस में ज्यादा प्रभावी रहती है जिनके लक्षण अक्सर कम स्टेज में दिखाई नहीं देते है। कुछ टेस्ट और चेक अप के तरीके काफी आसानी से उपलब्ध होते हैं और सस्ते भी रहते हैं इसलिए आपको चेक अप करवाने में हमेशा आगे रहना चाहिए। आइए जान लेते हैं इस स्थिति के बारे में।

अर्ली डिसीस डिटेक्शन का महत्तव

यह प्रक्रिया काफी जरूरी होती है क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज शुरू करने से पहले उसको पकड़ना जरूरी होता है। अगर बीमारी ज्यादा फैलने से पहले ही पकड़ में आ जाती है तो समय रहते ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है और उस को नियंत्रित करने में आपके डॉक्टर सफल हो सकते हैं। मरीज को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है और इलाज में ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। इसलिए आपको हर साल अपने मेडिकल चेक अप जरूर करवाते रहने चाहिए ताकि किसी भी बीमारी की अगर शुरुआत आपके शरीर में हो रही हो तो वह समय से ही पकड़ में आ सके।

अर्ली डिसीस डिटेक्शन के लाभ

इसके होने से मरीजों की जान बचाई जा सकती है क्योंकि समय से बीमारी का डायग्नोसिस होने से बीमारी पर पहले ही नियंत्रण कर लिया जाता है जिस वजह से सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। मृत्यु दर को कम करने में भी अर्ली डिसीस डिटेक्शन ने काफी सहयोग दिया है। मरीज को संतुष्टि मिल जाती है की उसका इलाज संभव है और उसने समय से ही इलाज शुरू करवा लिया है।

अर्ली डिसीस डिटेक्शन में किन किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है?

मेडिकल इमेजिंग : बहुत सारी मेडिकल इमेजिंग जैसी तकनीकों का बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे x रे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI आदि।

अन्य टेस्ट : अन्य बहुत सारे टेस्ट जैसे लैब में होने वाले टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें नियमित रूप से होने वाले चेक अप आदि शामिल होते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा AI और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का प्रयोग करके भी कुछ टेस्ट आदि किए जाते हैं।

अर्ली डिसीस डिटेक्शन में तकनीक का रोल

आज के समय में तकनीक आगे बढ़ती ही जा रही है और डॉक्टरों के पास उपलब्ध यंत्रों और टूल्स का भी तकनीकीकरण और एडवांसमेंट हो रहा है जोकि एक अच्छी बात है। अर्ली डिसीस डिटेक्शन में भी तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के समय में AI और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का प्रयोग काफी मुश्किल जगहों का डायग्नोस करना भी संभव हो पा रहा है।

क्या अर्ली डिसीस डिटेक्शन में कोई चुनौती भी है?

मरीजों के लिए इसमें चुनौतियां आ सकती हैं जैसे डॉक्टरों तक पहुंचना या फिर उन्हें इतनी जागरूकता नहीं मिलती है की वह अपना समय से रेगुलर चेक अप करवाते रहें। आमतौर पर भारत में लोग तब ही अस्पताल जाते हैं जब उन्हें कोई लक्षण दिखता है। इसके अलावा तकनीकीकरण के कारण खर्चे में काफी बढ़ोतरी होती जा रही है जिससे प्रभावी तरीके डॉक्टरों तक उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं।

लड़कों के वॉर्डरोब में होने चाहिए इन 6 रंगों की शर्ट, लड़कियां स्टाइल देखकर फिदा हो जाएगी

जब आप शर्ट का रंग चुनते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं किस कलर की शर्ट पहनना अच्छा होता है। अब ज्यादा सोचने की जरुरत नहीं है। हम इस आर्टिकल में बताएंगे कि लड़कों पर किस रंग की शर्ट अच्छी लगेगी।

अगर आप भी ट्रेंडी कलर की शर्ट पहनना पसंद करते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। चाहे डेली वियर हो या फिर कोई ऑकेजन, ऐसे में लड़के शर्ट पहनना पसंद करते हैं। अक्सर शर्ट के रंग को लेकर लड़के काफी कंफ्यूज रहते हैं। शॉपिंग के दौरान किस कलर की शर्ट लेनी जो उनके लुक को सूट करेगी। जब आप शर्ट का चयन करते हैं तो कलर का ध्यान रखना जरुरी होता है। शर्ट का रंग हमारे पर्सनालिटी को शानदार बनाता है। एक अच्छे रंग की शर्ट लुक में चार चांद लगा देता है वहीं, गलत रंग की शर्ट लेने से ओवरऑल लुक को खराब कर देती है। अगर आप इन रंग की शर्ट पहनेंगे तो स्मार्ट दिखेंगे, लड़कियां भी तारीफ करेंगी।

ब्लैक शर्ट

लड़कों को अपनी वॉर्डरोब में एक बेसिक ब्लैक शर्ट जरुर होनी चाहिए। किसी भी ऑकेजन पर ब्लैक शर्ट काफी सुंदर लगती है। यह हमेशा एकदम क्लासी लुक देता है। यह रंग हर स्किन टोन पर सूट करता है।

व्हाइट शर्ट

व्हाइट शर्ट दिखने में सिंपल हो सकती है लेकिन यह लुक को बेहद कमाल कर देती है। इसको आप रोजाना या किसी खास ऑकेजन पर पहन सकते हैं। इसे आप कई तरह से फैशन एक्सपेरिमेंट कर के न्यू लुक क्रिएट कर पहन सकते हैं।

लाइट पिंक शर्ट

यदि आप यह सोचते हैं कि पिंक कलर लड़कियों के लिए है तो आपको अपना टेस्ट बदलने की काफी जरुरत है। सॉफ्ट पिंक कलर लड़कों पर खूब जचते हैं। लड़कियों को लड़को पर पिंक यह रंग काफी पसंद आता है। अगर आप किसी रोमेंटिक डेट पर जाना हो या अपनी क्रश को इंप्रेस करना हो, इस रंग से बेहतर कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता।

पाउडर ब्ल्यू शर्ट

इस रंग की शर्ट काफी ट्रेंड में रहती है। पाउडर ब्ल्यू शर्ट दिखने में बेहद क्लासी लगती है और प्रोफेशनल लुक भी देती है। यह शर्ट हर किसी के स्किन टोन पर सूट करती है। इसे आप ऑफिस से लेकर डेट पर भी वियर कर सकते हैं।

ऑलिव ग्रीन शर्ट

ऑलिव ग्रीन शर्ट तो आजकल ट्रेंड में है और यह कलर लड़कों पर खिल के आता है। इस रंग की खूबी है कि ये आपको सबसे अलग दिखाता है। ऑलिव ग्रीन शर्ट आपके वॉर्डरोब में जरुर होनी चाहिए। यह कलर लड़कियों को खूब पसंद आता है।

मैरुन कलर

इन रंगों से हटकर आप मैरुन कलर जरुर ट्राई करें। यह रंग हर स्किन टोन पर मैच करता है और आपके लुक को भी काफी स्टाइलिश बनाता है। मैरुन शर्ट को ब्लैक पेंट या जींस के साथ पहन सकते हैं या फिर व्हाइट फॉर्मल पेंट के साथ मैरुन शर्ट एकदम खिल के नजर आती है।

फिट रखने में सहायक है लेटरल बैंड वॉक, जानिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

लेटरल बैंड वॉक एक अहम एक्सरसाइज है, जो कूल्हों की स्थिरता और ताकत को बढ़ाने में मदद करता है।यह एक्सरसाइज खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो दौड़ते, खेलते या काम के कारण लंबे समय तक खड़े रहते हैं।इस लेख में हम लेटरल बैंड वॉक के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसे कैसे सही तरीके से किया जा सकता है और इसे करते समय क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए।

लेटरल बैंड वॉक का महत्व

लेटरल बैंड वॉक कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करने का एक बेहतरीन तरीका है।यह ग्लूटस मेडियस और मिनिमस मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जो कूल्हों की स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।इसके नियमित अभ्यास से न केवल चोट लगने का खतरा कम होता है बल्कि शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है और चलने-फिरने में आसानी होती है।यह एक्सरसाइज खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो दौड़ते हैं या खेल खेलते हैं।

लेटरल बैंड वॉक करने का तरीका

लेटरल बैंड वॉक करते समय सही तकनीक अपनाना बहुत जरूरी है।सबसे पहले अपने पैरों के चारों ओर एक रेजिस्टेंस बैंड बांधें और घुटनों को हल्का मोड़ें, फिर धीरे-धीरे एक पैर को साइड में उठाएं और दूसरे पैर को उसके पास लाएं। इस प्रक्रिया को दूसरी दिशा में दोहराएं।ध्यान रखें कि आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए और पेट अंदर खींचा हुआ होना चाहिए।

नियमित अभ्यास करें

लेटरल बैंड वॉक का अधिकतम लाभ पाने के लिए इसे नियमित रूप से करना जरूरी है। सप्ताह में कम से कम तीन बार इस एक्सरसाइज का अभ्यास करें।हर सेट में 10-15 कदम लें और धीरे-धीरे इसकी संख्या बढ़ाते जाएं। शुरुआत में हल्के रेजिस्टेंस वाले बैंड का उपयोग करें ताकि आप आसानी से इसे कर सकें।सही तकनीक अपनाना भी जरूरी है ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके और किसी प्रकार की चोट से बचा जा सके।

अन्य एक्सरसाइज के साथ संयोजन

लेटरल बैंड वॉक को अन्य एक्सरसाइज के साथ मिलाकर करने से इसका प्रभाव बढ़ जाता है।स्क्वाट्स, लंजेस और ग्लूट ब्रिज जैसी एक्सरसाइज भी कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।इन सभी एक्सरसाइज का संयोजन आपके फिटनेस स्तर को बेहतर बनाएगा और आपकी कूल्हों की स्थिरता को और भी बढ़ाएगा।नियमित अभ्यास से न केवल आपकी ताकत बढ़ेगी बल्कि चोट लगने का खतरा भी कम होगा और आपका शरीर संतुलित रहेगा।

इस एक्सरसाइज को करते समय बरतें ये सावधानियां

लेटरल बैंड वॉक एक सुरक्षित एक्सरसाइज माना जाता है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। अगर आपको किसी प्रकार का दर्द या असुविधा महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं और किसी विशेषज्ञ से सलाह लें।इसके अलावा शुरुआत में हल्के रेजिस्टेंस वाले बैंड का उपयोग करें ताकि आप आसानी से इसे कर सकें।इस प्रकार लेटरल बैंड वॉक न केवल आपके कूल्हों की स्थिरता बढ़ाता है बल्कि आपके पूरे शरीर की ताकत भी सुधारता है।

होम लोन के प्री-पेमेंट पर कितना देना होता है चार्ज

होम लोन का प्री–पेमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की दिशा में एक सही कदम हो सकता है, लेकिन यह तभी फायदेमंद साबित होगा जब आप इससे जुड़े सभी पहलुओं को ध्यानपूर्वक समझेंगे। आज के आर्टिकल में हम आपको यही बताने वाले हैं।

आज के दौर में कई लोग अपना घर खरीदने के लिए होम लोन का सहारा लेते हैं, जो एक बड़े खर्च को आसान मासिक किस्तों में बांटने का अवसर देता है। हालांकि, कई बार होम लोन का भारी ब्याज बोझ बन जाता है और लोग इसे समय से पहले चुकाने के बारे में सोचते हैं। होम लोन का प्री-पेमेंट एक ऐसा विकल्प है जो न केवल ब्याज के खर्च को कम कर सकता है, बल्कि लोन की अवधि से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में सहायक साबित हो सकता है।

क्या होता है इसका मतलब?

होम लोन प्री-पेमेंट का मतलब है कि लोन की अवधि पूरी होने से पहले ही कुछ हिस्सा चुका देना। जब आप लोन का एक हिस्सा समय से पहले चुकाते हैं, तो बैंक उस पर ब्याज कम कर देते हैं, जिससे कुल ब्याज खर्च में बचत होती है। इससे लोन जल्द खत्म हो सकता है और आप भविष्य में वित्तीय आजादी पा सकते हैं। हालांकि, प्री-पेमेंट से पहले इस विकल्प से जुड़े चार्ज और शर्तों को समझना जरूरी है।

क्या है जरूरी शर्त?

अक्सर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लोन प्री-पेमेंट पर एक पेनल्टी चार्ज लिया जाता है। यह चार्ज बकाया राशि का एक प्रतिशत या एक फ्लैट शुल्क हो सकता है, जो लोन के शुरुआती वर्षों में लागू किया जाता है। कुछ बैंक प्री-पेमेंट को बिना पेनल्टी के अनुमति देते हैं, लेकिन इसके लिए ब्याज की कुल गणना पर निर्भर करता है। लोन के एग्रीमेंट में इस बात का जिक्र होता है, इसलिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले इन शर्तों को पढ़ना चाहिए।

मिलता है ये फायदा

होम लोन प्री-पेमेंट करने से ब्याज पर होने वाला अतिरिक्त खर्च बच सकता है और आपकी मासिक किस्तें कम हो जाती हैं, जिससे आप राहत महसूस कर सकते हैं। हालांकि, यह फैसला लेते समय इमरजेंसी फंड का ध्यान रखना चाहिए। प्री-पेमेंट करते समय अगर आप अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करते हैं, तो भविष्य में किसी आकस्मिक स्थिति में वित्तीय दिक्कतें हो सकती हैं।

प्री-पेमेंट से पहले रखें इस बात का ध्यान

होम लोन का प्री-पेमेंट करने से पहले पेनल्टी चार्ज और ब्याज पर संभावित बचत का कैलकुलेशन करना आवश्यक है। कई बार पेनल्टी की राशि इतनी होती है कि ब्याज पर होने वाली बचत की तुलना में यह अधिक बोझिल हो सकता है। इस वजह से सभी संभावित खर्चों का आकलन करके ही प्री-पेमेंट का निर्णय लेना चाहिए।

भारत का एयरोस्पेस बाजार 2035 तक 61 अरब डॉलर तक पहुंचेगा, एमएसएमई के लिए खुलेंगे बड़े अवसर : राम मोहन नायडू

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने गुरुवार को कहा कि भारत का एयरोस्पेस मार्केट वर्ष 2025 के 30 अरब डॉलर से अधिक के स्तर से बढ़कर 2035 तक लगभग 61 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसी अवधि में देश के वाणिज्यिक विमान बेड़े का आकार भी दोगुना से अधिक होकर करीब 2,050 विमानों तक पहुंच सकता है, जिससे भारतीय विनिर्माण कंपनियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए वैश्विक एयरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का बड़ा अवसर पैदा होगा।

सीआईआई और नागर विमानन मंत्रालय की संयुक्त पहल वोर्टेक्स 2026 को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि सरकार भारत में एक मजबूत एयरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता एवियोनिक्स क्षेत्र में अवसर तलाश सकते हैं, प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनियां एयरोस्पेस कलपुर्जों के निर्माण में प्रवेश कर सकती हैं और ऑटोमोबाइल उद्योग को आपूर्ति करने वाले एमएसएमई भी एयरोस्पेस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के ऑटो कंपोनेंट उद्योग, जिसका आकार आज लगभग 70 अरब डॉलर है, और मोबाइल फोन विनिर्माण क्षेत्र की सफलता एयरोस्पेस उद्योग के लिए प्रेरणादायक उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि आज भारत में उपयोग होने वाले लगभग 99 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही निर्मित हो रहे हैं और इसी तरह की सफलता एयरोस्पेस क्षेत्र में भी हासिल की जा सकती है।

मंत्री ने कहा कि एमएसएमई निर्यात में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में जहां यह लगभग 4 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2025 तक बढ़कर 12.4 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। वर्तमान में 1.73 लाख से अधिक एमएसएमई सीधे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एयरोस्पेस क्षेत्र की आवश्यकताओं का लगभग 80 प्रतिशत आधार भारतीय उद्योग के पास पहले से मौजूद है और शेष 20 प्रतिशत के लिए सरकार आवश्यक नियामकीय सहयोग प्रदान करेगी।

नायडू ने बताया कि भारतीय एयरलाइंस ने कुल 1,640 विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में लगभग 80 करोड़ पुर्जों और कलपुर्जों की आवश्यकता होगी। यह भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक विशाल अवसर है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2035 तक भारत में हवाई यात्री यातायात में औसतन 8.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि दर होगी। उनके अनुसार, एयरोस्पेस ऐसा क्षेत्र है जहां तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार और भारत में आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण की तलाश कर रही वैश्विक कंपनियां, दोनों एक साथ अवसर प्रदान कर रही हैं।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि केवल भारत की जरूरतें ही नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार भी भारतीय उद्योग के लिए बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने बताया कि दुनिया की दो सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनियों एयरबस और बोइंग के पास वर्तमान में 15,000 से अधिक वाणिज्यिक विमानों के ऑर्डर हैं। इससे भारतीय एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर पुर्जे और घटक आपूर्ति करने का अवसर मिल सकता है।

इस बीच, नागर विमानन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि भारत पहले ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश में परिचालित हवाईअड्डों की संख्या 74 थी, जो अब बढ़कर 166 हो चुकी है। इसी अवधि में विमान बेड़ा लगभग 350 विमानों से बढ़कर 874 विमानों तक पहुंच गया है। आने वाले दो दशकों में भारतीय विमानन बेड़े में 2,000 से अधिक नए विमान शामिल होने की उम्मीद है।

सिन्हा ने कहा कि लगभग 29,000 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान वाली संशोधित उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाईअड्डों और 200 आधुनिक हेलिपैड के विकास के माध्यम से विमानन पारिस्थितिकी तंत्र का और विस्तार किया जाएगा।

वहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अध्यक्ष विपिन कुमार ने कहा कि भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप पहले से ही वैश्विक बाजार को हर वर्ष 18,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के विमान कलपुर्जे उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्री यातायात में वृद्धि से विमान, कलपुर्जों, एमआरओ सेवाओं, ग्राउंड सपोर्ट उपकरण, नेविगेशन प्रणालियों, हवाईअड्डा प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण सुविधाओं और डिजिटल समाधानों की मांग लगातार बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि एएआई विमानन अवसंरचना और कनेक्टिविटी के विस्तार के माध्यम से इस पहल को समर्थन देगा तथा भारतीय तकनीकों को हवाईअड्डा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

वहीं, बोइंग इंडिया एवं दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और सीआईआई राष्ट्रीय एयरोस्पेस विनिर्माण समिति के अध्यक्ष सलिल गुप्ते ने कहा कि बोइंग के भारत में 300 आपूर्तिकर्ता साझेदार हैं, जिनमें से लगभग 25 प्रतिशत एमएसएमई हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि भारत एयरोस्पेस उत्पाद बना सकता है या नहीं, क्योंकि यह पहले से हो रहा है। असली सवाल यह है कि भारत इस क्षमता का विस्तार कितनी तेजी से कर सकता है।

22 साल से फ्रीज था भ्रूण : ग्रीस में 54 साल की महिला फिर से बनी मां, पिछले साल खोया था बेटा अब उसी पर रखा नाम

एथेंस, एजेंसी। अपने सबसे कठिन दौर से उबरते हुए, एक ग्रीक दंपति ने इस सप्ताह जन्मे बच्चे के साथ एक नई शुरुआत की। ऐसा करने के लिए उन्हें क्रिस्टीना राप्ती-त्जेलेपी के दशकों पुराने भ्रूणों में से एक का उपयोग करना पड़ा। इसके साथ ही सरकारी समय सीमा से पहले ही बच्चे को जन्म देना पड़ा।

अक्तूबर में एक सड़क दुर्घटना में अपने 21 वर्षीय बेटे की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद, अब 54 वर्षीय राप्ती-त्जेलेपी और उनके पति ने 22 वर्षों से जमे हुए भ्रूण का उपयोग करके एक और प्रयास करने का निर्णय लिया। राप्टी-त्जेलेपी को महिलाओं के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) प्रक्रिया पूरी करने और राष्ट्रीय अथॉरिटी से मंजूरी पाने की ग्रीक सरकार की 54 साल की उम्र सीमा का सामना करना पड़ रहा था। जब उन्होंने शुरुआत की, तो समय पहले ही कम पड़ रहा था।

उन्होंने कहा, 'मेरे पास सिर्फ ढाई महीने का समय था। यह तनावपूर्ण था, लेकिन अंदरूनी हिम्मत और हमारे डॉक्टर व उनकी पूरी टीम के साथ होने की वजह से हमने हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने बुधवार को ग्रीस की राजधानी एथेंस में एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका वजन 3.49 किलोग्राम था। शुक्रवार को गुलाबी गुब्बारों और फूलों से सजे अस्पताल के कमरे में नए माता-पिता भावुक हो गए।

काले पजामे में बिस्तर पर बैठीं राप्टी-त्जेलेपी ने कहा, 'हमने जिंदगी को एक और मौका देने, नई शुरुआत करने, अपने घर में नई जिंदगी लाने और अपने परिवार की कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मेरी इच्छा है कि वह स्वस्थ और खुश रहे, हमारे पहले बच्चे की तरह खुशियों से भरी रहे, जिसने हमारे घर को हंसी-खुशी से भर दिया था।' यह बच्चा महिला के उस भ्रूण से पैदा हुआ था जिसे 22 साल से भी ज्यादा समय पहले फ्रीज किया गया था। प्रेग्नेंसी के लिए फ्रीज किए गए फर्टिलाइज्ड अंडे का इस्तेमाल करने के मामले में यह बहुत लंबा समय है। पिछले साल, ओहियो के एक जोड़े ने 'एम्ब्रियो अडॉप्शन' (भ्रूण गोद लेने) की प्रक्रिया के जरिए 30 साल से ज्यादा समय तक फ्रीज किए गए भ्रूण से पैदा हुए एक बच्चे का स्वागत किया था और उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से पहचान मिली थी। राप्टी-त्जेलेपी के स्त्री रोग विशेषज्ञ और हेलेनिक सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के प्रमुख डॉ. कोस्टास पैंटोस ने तर्क दिया कि ग्रीस में उम्र की पाबंदियों पर फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि देश में जन्म दर तेजी से गिर रही है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के रहने वाले पैंटोस ने कहा, 'कानून बहुत सख्त है। 54 साल और एक दिन की उम्र भी मंजूर नहीं है। शायद अब इसे बदलने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा अधिकार है जिससे माता-पिता को वंचित नहीं किया जाना चाहिए।'

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सऊदी अरब ने बंद की ऑयल पाइपलाइन

सऊदी, एजेंसी। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के बाद अपनी ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है। यह पाइपलाइन देश के पूर्वी तेल उत्पादक इलाकों से कच्चा तेल लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे सऊदी अरब होर्मुज स्ट्रेट से बचकर दुनिया के बाजारों तक तेल पहुंचाता है। गुरुवार को कई ड्रोन ने पाइपलाइन को निशाना बनाया। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि पाइपलाइन को सुरक्षा के लिहाज से अस्थायी रूप से बंद किया गया है।

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, हमले में रास्ते के कई पंपिंग स्टेशन क्षतिग्रस्त हुए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में एक स्टेशन पर आग से बड़े नुकसान और दूसरे स्थान से काला धुआं उठता दिखाई दिया।

सऊदी विदेश मंत्रालय ने बताया कि ड्रोन इराक से आए थे और हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। कुछ नुकसान भी हुआ है, जिसकी मरम्मत की जा रही है। सऊदी अरब ने कहा कि इराकी प्रधानमंत्री के अनुरोध पर वह फिलहाल जवाबी हमला नहीं करेगा, ताकि इराक सरकार को अपनी जमीन से होने वाले हमलों को रोकने का मौका मिल सके। इराक ने भी हमले की निंदा करते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

ईरानी हमलों के कारण होर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही लगभग बंद है। ऐसे समय में ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। जून की शुरुआत तक इस पाइपलाइन से यानबू तक तेल भेजना बढ़कर 50 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा हो गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पंपिंग स्टेशनों की मरम्मत पाइपलाइन को ठीक करने की तुलना में आसान हो सकती है, लेकिन नुकसान की पूरी जानकारी अभी साफ नहीं है। इसी बीच सऊदी अरब ने OPEC को बताया कि उसका कच्चे तेल का उत्पादन पिछले महीने 1990 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया।

हूतियों ने भी कब्जाया अहम द्वीप

दूसरी ओर, यमन के हूती लड़ाकों ने मायून द्वीप (पेरिम द्वीप) पर कब्जा कर लिया है। यह छोटा ज्वालामुखीय द्वीप बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट के बीच स्थित है, जो दुनिया के अहम समुद्री रास्तों में शामिल है। हूतियों ने गुरुवार को करीब 80 किमी दूर मोचा शहर पर भी कब्जा किया था। बाब-अल-मंदेब से जहाजों की आवाजाही पहले ही 2023 के आखिर से हूती हमलों के बाद करीब 60% घट चुकी है। अब इस रास्ते पर खतरा बढ़ने से सऊदी अरब को तेल की सप्लाई के लिए लंबा रास्ता अपनाना पड़ सकता है।

तेल 100 डॉलर के पार

इन घटनाओं के बीच कच्चे तेल की कीमत इस हफ्ते फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इससे ईरान को भविष्य की बातचीत में अतिरिक्त दबाव बनाने की ताकत मिल सकती है। ईरान ने हूतियों का खुलकर समर्थन किया है। उसके विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब से हूती नियंत्रित इलाकों की नाकाबंदी खत्म करने और बातचीत शुरू करने की अपील की है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक प्रवक्ता ने यहां तक कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में यमन को शामिल करना होगा।

9/11 की 25वीं बरसी पर अल कायदा ने दिखाया ओसामा के बेटे का वीडियो, 7 साल पहले अमेरिका ने घोषित किया था मृत

न्यूयॉर्क, एजेंसी। 11 सितंबर 2001... ये वो तारीख है जिसे अमेरिका कभी नहीं भुला सकता है। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे भयानक और जख्म देने वाला दिन है। आज से ठीक 25 साल पहले अल-कायदा के आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाकर ऐसा तांडव मचाया, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आज भी इस दिन को याद कर वो खौफनाक मंजर आंखों के सामने छा जाता है। इस बीच 9/11 की 25वीं बरसी पर अल-कायदा ने ओसामा के बेटे का एक वीडियो जारी किया है, जिसे 7 साल पहले अमेरिका ने मृत घोषित किया था।

11 सितंबर के हमलों की 25वीं बरसी पर, अल-कायदा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हमजा बिन लादेन को दिखाया गया है। हमजा अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का बेटा और नामित उत्तराधिकारी है, जिसे कथित तौर पर 2019 में अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अभियान में मार दिया गया था। यह फुटेज अल-कायदा के आधिकारिक मीडिया विंग अस-सहब द्वारा 11 सितंबर, 2001 के हमलों की 25वीं बरसी के अवसर पर जारी किया गया। इसका शीर्षक 'ए क्वार्टर सेंचुरी ऑफ द 11 सितंबर रेड्स' रखा गया है। इस वीडियो में हमजा की मौजूदगी ने खुफिया विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि वह अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर मारा गया था। 50 मिनट के इस वीडियो में हमजा कई बार दिखाई देता है। इसके अलावा वीडियो में अल-कायदा के पूर्व प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी की कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, जो पहले सार्वजनिक नहीं हुई थीं।

बघाई ने पीट हेगसेथ के बयान पर बोला हमला, कहा- 9/11 की आड़ में ईरान के खिलाफ जंग को सही ठहरा रहा अमेरिका

वॉशिंगटन, एजेंसी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने वाशिंगटन के रुख पर कड़ा एतराज जताते हुए अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमलों की 25वीं बरसी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ एक 'लापरवाह और गैर-कानूनी युद्ध' को सही ठहराने के लिए कर रही है। बघाई ने अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के उस बयान की कड़ी निंदा की, जो उन्होंने 9/11 के एक स्मृति समारोह के दौरान दिया था। ईरानी प्रवक्ता ने अमेरिकी विदेश नीति के बुनियादी अंतर्विरोधों पर सवाल उठाते हुए आतंकवाद की परिभाषा तय करने के वाशिंगटन के 'अकेले अधिकार' को खारिज कर दिया।

बघाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि 9/11 हमले के जिम्मेदार लोग ईरानी नहीं थे। उन्होंने अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका खुद दूसरे देशों में सैन्य कार्रवाई करता है, अधिकारियों की हत्या करता है और आम नागरिकों को निशाना बनाता है, फिर भी आतंकवाद की परिभाषा तय करने का अधिकार अपने पास रखता है। ऐतिहासिक दावों का खंडन करते हुए बघाई ने स्पष्ट किया कि 2001 के हमलों में ईरान की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कहा कि 9/11 के हमलावर ईरानी नहीं थे, बल्कि ये वही लोग थे जिन्हें पिछले दशकों में खुद अमेरिका ने हथियार दिए, संगठित किया और तैयार किया था।

बघाई ने कहा कि 9/11 के बाद अमेरिका के तथाकथित 'आतंक के खिलाफ युद्ध' ने इराक और अफगानिस्तान में केवल दशकों का कब्जा, विनाश और निर्दोष नागरिकों की मौतें दीं। उन्होंने हेगसेथ के इस रुख को पूरी तरह बेतुका बताते हुए कहा कि किसी संप्रभु देश के अधिकारियों की हत्या करने और महिलाओं व बच्चों सहित आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले आपराधिक युद्ध को आतंकवाद-निरोध के नाम पर नैतिक रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। बघाई ने अमेरिकी नीति का मजाक उड़ाने के लिए फिल्म 'डेस्पिकेबल मी' का लोकप्रिय 'ग्रूज प्लान' मीम भी साझा किया।

पीट हेगसेथ ने क्या कहा था?

दूसरी तरफ, अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने अपने आक्रामक भाषण में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमेरिका के आतंकवाद-विरोधी अभियान से जोड़ा था। हेगसेथ ने दावा किया कि पिछले छह महीनों में अमेरिकी सैनिकों ने आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजक को तहस-नहस कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरानी नेताओं को मार गिराया है, उनकी वायुसेना को तबाह किया है और उनकी नौसेना व तेल टैंकरों को समुद्र में डुबो दिया है। हेगसेथ ने जोर देकर कहा कि अमेरिका जलडमरूमध्य पर नियंत्रण रखता है, आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। उन्होंने बाइबिल के वचनों और फ्लाइट 93 के यात्री टॉड बीमर के प्रसिद्ध शब्दों 'लेट्स रोल' का हवाला देते हुए इस लड़ाई को खत्म करने का संकल्प जताया। गौरतलब है कि 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के 19 आतंकियों ने चार यात्री विमानों का अपहरण कर अमेरिका पर हमला किया था। दो विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, तीसरा विमान वर्जीनिया स्थित पेंटागन से टकराया और चौथा विमान यात्रियों के विरोध के बाद पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अमेरिकी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस भीषण आतंकी हमले में 2,977 लोग मारे गए थे।

गुंडा एक्ट उत्पीड़न का हथियार नहीं, यूपी पुलिस को फटकार गोंडा के जाहिद अली पर इलाहाबाद होई कोर्ट ने कार्रवाई की रद्द

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में UP Control of Goondas Act, 1970 के इस्तेमाल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के रवैये पर बेहद कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने गोंडा निवासी जाहिद अली के खिलाफ Goondas Act के तहत की गई कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा कि इस तरह के शक्तिशाली कानून का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को परेशान करने या उत्पीड़न के हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि उसके सामने लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, जिनसे ये प्रतीत होता है कि राज्य सरकार Goondas Act को उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के अपने रवैये पर कायम है।

गोंडा जिला प्रशासन ने 11 मई 2026 को जाहिद अली के खिलाफ Goondas Act के तहत कार्रवाई की थी। उन्हें गुंडा घोषित करते हुए 6 महीने के लिए गोंडा जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि जाहिद अली के खिलाफ जिस 2010 के मुकदमे को कार्रवाई का आधार बनाया गया था, उसमें वह 2017 में ही बरी हो चुके थे। कोर्ट ने पाया कि इसके बावजूद पुलिस रिपोर्ट में पुराने मुकदमे को इस तरह प्रस्तुत किया गया, जिससे जाहिद की स्थिति को लेकर गलत तस्वीर सामने आती थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उसकी संलिप्तता को उसके बरी हो जाने के बाद उसे गुंडा घोषित करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक लंबित मुकदमा आदतन अपराधी होने का सबूत नहीं है। हाई कोर्ट ने साल 2020 के मुकदमे को भी Goondas Act लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी व्यक्ति के खिलाफ एक मुकदमा लंबित होना यह साबित नहीं करता कि वो आदतन अपराधी है।

इसके अलावा 2020 के मुकदमे और 2026 में Goondas Act के तहत कार्रवाई के बीच करीब 6 साल का अंतर था। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे अंतराल के बाद कार्रवाई करने के लिए आवश्यक reasonable nexus यानी उचित संबंध दिखाई नहीं देता।

बीट रिपोर्ट पर भी कोर्ट ने उठाए सवाल

पुलिस ने एक बीट सूचना रिपोर्ट को भी जाहिद के खिलाफ कार्रवाई का आधार बनाया था। लेकिन कोर्ट ने पाया कि उस सूचना के आधार पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। साथ ही, जाहिद को उस आरोप पर अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर भी नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसी पुलिस रिपोर्ट को उसके खिलाफ Goondas Act की कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।

पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट की गंभीर टिप्पणी

कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस को ये पता होना चाहिए था कि जाहिद अली वर्ष 2010 के मामले में 2017 में ही बरी हो चुके हैं। इसके बावजूद उस मामले को पुलिस रिपोर्ट में शामिल किया गया।

Goondas Act बहुत शक्तिशाली कानून, सावधानी से हो इस्तेमाल

हाईकोर्ट ने कहा कि Goondas Act एक बहुत शक्तिशाली कानून है। इसका इस्तेमाल सामान्य आपराधिक मामलों में या किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे कानून का इस्तेमाल बहुत सावधानी और सीमित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, खासकर तब जब संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों से वास्तव में सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) को खतरा हो।

हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई की रद्द

मामले में हाईकोर्ट ने जाहिद अली को राहत देते हुए उन्हें गुंडा घोषित करने का आदेश रद्द कर दिया। गोंडा जिले से 6 महीने के externment का आदेश रद्द कर दिया। कमिश्नर द्वारा उनकी अपील खारिज करने का आदेश भी रद्द कर दिया। इस तरह जाहिद अली के खिलाफ Goondas Act के तहत की गई पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट ने खत्म कर दी।

नई नवेली दुल्हन यामी गौतम पर होगा डायन होने का शक, दशहरे पर रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम एक बिल्कुल अलग अंदाज में दर्शकों के सामने आने वाली हैं। उनकी अगली फिल्म नई नवेली की घोषणा हो चुकी है और इसकी पहली झलक ने कहानी को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। फिल्म में यामी एक ऐसी दुल्हन का किरदार निभाएंगी, जो अपने नए परिवार की जिंदगी को खुशियों से भर देती है। कहानी में असली मजा तब आता है, जब परिवार का एक सदस्य उसी दुल्हन पर शक करने लगता है।

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और कलर येलो ने फिल्म की घोषणा करते हुए इसकी रिलीज डेट की भी जानकारी दी है। नई नवेली 16 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की पहली झलक साझा करके कैप्शन में लिखा, नई नवेली दुल्हन (डायन), इस दशहरे इंडिया की अपनी फैंटेसी फैमिली-एंटरटेनर फिल्म के लिए तैयार हो जाएं।

इस छोटी सी झलक के साथ ही फिल्म की कहानी को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। फिल्म की कहानी एक ऐसी दुल्हन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो देखने में बिल्कुल आदर्श लगती है। वह मेरठ के एक ऐसे परिवार में पहुंचती है, जहां पहले से ही काफी उथल-पुथल है। अपनी समझदारी और प्यार से वह इस बिखरे हुए परिवार को खुशहाल बनाने की कोशिश करती है।

देखते ही देखते जिस घर में परेशानियां थीं, वहां खुशियां आने लगती हैं। इसी बीच उसके देवर को अपनी भाभी पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि इतनी अच्छी और परफेक्ट भाभी के पीछे कोई राज जरूर है और कहीं वह वास्तव में डायन तो नहीं। यही शक फिल्म की कहानी को हास्य और रोमांच से जोड़ता है।

नई नवेली का निर्देशन बालाजी मोहन कर रहे हैं। फिल्म की पटकथा हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है। फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार जी. वी. प्रकाश कुमार ने तैयार किया है। निर्माता आनंद एल राय ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, नई नवेली ऐसी कहानी है, जो हर मोड़ पर दर्शकों को चौंकाती है।

जब मैंने हिमांशु शर्मा के साथ पहली बार इस कहानी पर चर्चा की, तो हमें इसका विचार काफी पसंद आया। फिल्म परिवार को केंद्र में रखते हुए फैंटेसी, हास्य और रोमांच को एक साथ लेकर चलती है। आनंद एल राय ने यामी गौतम को फिल्म के लिए बिल्कुल सही चुनाव बताया। उन्होंने कहा, यामी के अंदर इस किरदार को निभाने के लिए सारे गुण हैं।

प्राइम वीडियो इंडिया और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के एसवीओडी ओरिजिनल्स के निदेशक एवं प्रमुख निखिल मधोक ने भी यामी गौतम और फिल्म की टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यामी शानदार अभिनेत्री हैं और फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। उन्होंने आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा के साथ इस पहली साझेदारी को भी खास बताया।

'मिर्जापुर द मूवी' की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, छह दिन में कमाए 137 करोड़, वेलकम टू द जंगल के उड़ाए परखच्चे

पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा और रवि किशन जैसे सितारों से सजी फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने प्रदर्शन के शुरुआती तीन दिनों में ही अपनी लागत निकाल ली थी और अब यह मुनाफे की ओर तेजी से बढ़ रही है। सप्ताह के बीच के दिनों में भी फिल्म की कमाई की रफ्तार बरकरार है।

अमेजन प्राइम वीडियो की लोकप्रिय वेब श्रृंखला 'मिर्जापुर' पर आधारित इस फिल्म ने पहले ही दिन शानदार शुरुआत करते हुए 25.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 36 करोड़ रुपये का कारोबार किया। चौथे दिन इसकी कमाई 16 करोड़ रुपये रही, जबकि पांचवें दिन फिल्म ने 15.60 करोड़ रुपये जुटाए।

प्रारंभिक कारोबार के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने प्रदर्शन के छठे दिन यानी बुधवार को करीब 11.80 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके साथ ही भारत में फिल्म का छह दिनों का कुल शुद्ध कारोबार 137.15 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

फिल्म की कमाई पर नजर डालें तो 'मिर्जापुर द मूवी' ने पहले दिन से ही लगातार दोहरे अंक में कारोबार किया है। सप्ताह के कामकाजी दिनों में भी दर्शकों की अच्छी संख्या सिनेमाघरों तक पहुंच रही है। यही वजह है कि फिल्म जल्द ही 150 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने की ओर बढ़ रही है।

'मिर्जापुर द मूवी' को 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के लिए अब करीब 13 करोड़ रुपये और कमाने होंगे। फिल्म की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि सातवें दिन ही यह उपलब्धि हासिल हो सकती है। फिल्म ने कमाई के मामले में कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। 'मिर्जापुर द मूवी' ने 'कॉकटेल 2' के 104.53 करोड़ रुपये के कुल जीवनकाल कारोबार को पहले ही पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद फिल्म ने 'वेलकम टू द जंगल' के 134.11 करोड़ रुपये के कुल कारोबार को भी मात दे दी।

137.15 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ 'मिर्जापुर द मूवी' अब इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में आठवें स्थान पर पहुंच गई है। फिल्म की कमाई की रफ्तार बनी रही तो आने वाले दिनों में इसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है।

'मिर्जापुर द मूवी' लोकप्रिय वेब श्रृंखला 'मिर्जापुर' पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। यह फिल्म 4 सितंबर, 2026 को हिंदी और तेलुगु भाषाओं में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, अभिषेक बनर्जी, रवि किशन, जितेंद्र कुमार, रसिका दुग्गल, श्रिया पिलगांवकर और श्वेता त्रिपाठी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

फिल्म का निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने किया है। निर्माण में अमेजन एमजीएम स्टूडियोज का भी सहयोग है। फिल्म की शुरुआती कमाई को देखते हुए इसके आने वाले दिनों में और बेहतर कारोबार करने की उम्मीद जताई जा रही है।

'हनुमान अंश' की धुआंधार कमाई जारी, 34वें दिन 'टॉक्सिक' को पछाड़ा

नीम करौली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों भारतीय सिनेमाघरों में दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। फिल्म को रिलीज हुए पांच सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन इसके प्रति दर्शकों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि फिल्म की कमाई अब भी शानदार बनी हुई है। रिलीज के 34वें दिन फिल्म ने एक बार फिर दोहरे अंक में कमाई करते हुए कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं।

आमतौर पर ज्यादातर फिल्में पांचवें सप्ताह तक पहुंचते-पहुंचते सिनेमाघरों से लगभग बाहर हो जाती हैं। वहीं, 'हनुमान अंश' एक महीने बाद भी प्रतिदिन 10 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर रही है, जो अपने आप में उल्लेखनीय है। हालांकि फिल्म के शुरुआती दो सप्ताह अपेक्षाकृत धीमे रहे थे, लेकिन तीसरे सप्ताह से इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया और इसके बाद फिल्म ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

प्रारंभिक कारोबार के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 34वें दिन यानी पांचवें बुधवार को 10.25 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की। इसके साथ ही फिल्म ने पांचवें बुधवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों की सूची में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।

'हनुमान अंश' ने 'धुरंधर' के पांचवें बुधवार के 4.75 करोड़ रुपये के कारोबार को काफी पीछे छोड़ दिया। इस तरह फिल्म ने पांचवें बुधवार को सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

34वें दिन के कारोबार के बाद 'हनुमान अंश' का भारत में कुल शुद्ध कारोबार 153.13 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं फिल्म की कुल सकल कमाई 180.73 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

फिल्म की लगातार मजबूत कमाई ने इसे 2026 की सबसे सफल हिंदी फिल्मों की सूची में भी पहुंचा दिया है।

153.13 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई के साथ 'हनुमान अंश' ने रॉकिंग स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के हिंदी संस्करण को पीछे छोड़ दिया है। 'टॉक्सिक' के हिंदी संस्करण ने भारतीय सिनेमाघरों में 143.63 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

इस उपलब्धि के साथ 'हनुमान अंश' वर्ष 2026 में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों की सूची में छठे स्थान पर पहुंच गई है। अब फिल्म की नजर शीर्ष पांच में जगह बनाने पर है।

'हनुमान अंश' का अगला निशाना 'आवारापन 2' है, जिसने 156.02 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। 'हनुमान अंश' को शीर्ष पांच हिंदी फिल्मों की सूची में प्रवेश करने के लिए करीब 3 करोड़ रुपये और कमाने होंगे। फिल्म की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि 35वें दिन ही यह आंकड़ा पार हो सकता है।

'हनुमान अंश' की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए फिल्म का 200 करोड़ रुपये के शुद्ध कारोबार वाले क्लब में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। उम्मीद है कि छठे सप्ताहांत तक फिल्म यह उपलब्धि हासिल कर सकती है।

इसके बाद फिल्म की नजर 250 करोड़ रुपये के आंकड़े पर होगी। हालांकि पांचवें सप्ताह के बाद भी जिस तरह दर्शकों का उत्साह कायम है, उससे यह देखना दिलचस्प होगा कि छठे सप्ताह में 'हनुमान अंश' की कमाई किस स्तर तक पहुंचती है।

फिल्म की लगातार बढ़ती कमाई ने इसे इस वर्ष की सबसे चर्चित सफल फिल्मों में शामिल कर दिया है। अब दर्शकों और फिल्म कारोबार की नजर इसके अगले पड़ाव और 200 करोड़ रुपये के आंकड़े पर टिकी है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com